गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 066
दि. 05.07.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

‘क्या मैं मर गई हूं?’— असली तृणमूल विवाद के बीच ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन, खुद संभाली प्रदेश अध्यक्ष की कमान; बागियों को खुली चुनौती

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी सियासी उथल-पुथल के बीच शनिवार को पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फेसबुक लाइव के जरिए बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद संगठन में बढ़ते असंतोष, वरिष्ठ नेताओं के इस्तीफों, पार्टी कार्यालय को लेकर विवाद और ‘असली तृणमूल कांग्रेस’ के दावे के बीच ममता ने स्पष्ट कर दिया कि संगठन की कमान अब सीधे उनके हाथ में रहेगी। उन्होंने घोषणा की कि वह स्वयं पश्चिम बंगाल प्रदेश तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगी और संगठन को नए सिरे से मजबूत करेंगी।

करीब एक घंटे तक चले अपने संबोधन में ममता बनर्जी ने न केवल संगठनात्मक बदलावों का ऐलान किया, बल्कि पार्टी छोड़ने वाले नेताओं, बागी गुट और भारतीय जनता पार्टी पर भी तीखे हमले किए। उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि तृणमूल कांग्रेस का वास्तविक नेतृत्व अब भी उनके हाथ में है और पार्टी की पहचान किसी चुनाव चिह्न या भवन से नहीं, बल्कि जनता के भरोसे और कार्यकर्ताओं की ताकत से तय होती है।

फेसबुक लाइव के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय रूप से जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने स्वयं प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभालने का निर्णय लिया है ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके और कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखा जा सके। इसके साथ ही उन्होंने विधायक कुणाल घोष और पूर्व मंत्री मदन मित्रा को पार्टी का महासचिव नियुक्त करने की घोषणा भी की। माना जा रहा है कि इन नियुक्तियों के जरिए संगठन में नई सक्रियता लाने और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की रणनीति अपनाई गई है।

अपने संबोधन के दौरान ममता बनर्जी सबसे अधिक आक्रामक उस समय दिखाई दीं, जब उन्होंने ‘असली तृणमूल कांग्रेस’ को लेकर चल रही बहस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा, “आप क्या सोचते हैं? क्या मैं मर गई हूं?” इस एक वाक्य के जरिए उन्होंने अपने विरोधियों को स्पष्ट संदेश दिया कि जब तक वह सक्रिय राजनीति में हैं, तब तक तृणमूल कांग्रेस की असली पहचान और नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता।

उन्होंने कहा कि कुछ लोग चुनाव चिह्न और पार्टी के नाम को लेकर तरह-तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है। यदि कभी ऐसी स्थिति भी आ जाए कि चुनाव चिह्न किसी और के पास चला जाए, तब भी वह जनता के बीच जाकर अपना पक्ष रखेंगी और लोगों का समर्थन हासिल करेंगी। उनके अनुसार राजनीतिक दल की असली ताकत उसके कार्यकर्ता और जनता का विश्वास होता है, न कि केवल चुनाव चिह्न।

ममता बनर्जी ने 21 जुलाई को होने वाली तृणमूल कांग्रेस की पारंपरिक शहीद दिवस सभा को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में यह कार्यक्रम रद्द नहीं होगा। यदि प्रशासन अनुमति नहीं देता, तब भी सभा आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वह रिक्शे पर खड़े होकर भी जनता को संबोधित करेंगी। यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब पार्टी का आरोप है कि प्रशासन कोलकाता में अगस्त तक बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दे रहा है।

उन्होंने सवाल उठाया कि यदि रैलियों और सभाओं पर रोक लगाई जा रही है, तो क्या पूरे शहर में अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी गई है। ममता ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल विपक्षी राजनीतिक दलों को रोकने के लिए किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने इस संबंध में किसी विशेष अधिकारी का नाम नहीं लिया।

अपने भाषण में ममता बनर्जी ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो नेता आज तृणमूल कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, वे उसी पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव जीतकर विधानसभा और अन्य जनप्रतिनिधि संस्थाओं तक पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से मिलने वाली मान्यता, पार्टी का टिकट और जनता का समर्थन उन्हें तृणमूल कांग्रेस की वजह से मिला था, लेकिन अब वही लोग संगठन के खिलाफ खड़े हो गए हैं।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक हैं और किसी को अलग विचार रखने का अधिकार है, लेकिन विश्वासघात और बेईमानी को किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। उनके अनुसार व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण संगठन को नुकसान पहुंचाना जनता के विश्वास के साथ भी धोखा है।

ममता बनर्जी ने उन नेताओं को भी खुली चुनौती दी जिन्हें उन्होंने भाजपा की भाषा बोलने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यदि किसी नेता को वास्तव में भाजपा की विचारधारा पसंद है, तो उसे छिपकर राजनीति करने के बजाय खुलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। उन्होंने ऐसे नेताओं को गद्दार और बेवफा बताते हुए कहा कि पार्टी से सम्मान और राजनीतिक पहचान प्राप्त करने के बाद उसी संगठन के खिलाफ काम करना नैतिक रूप से गलत है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य के कुछ इलाकों में लोगों पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें पक्ष बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह उन सामान्य कार्यकर्ताओं या समर्थकों को दोष नहीं देतीं, क्योंकि कई लोगों के सामने परिवार चलाने और रोजगार बचाने जैसी मजबूरियां होती हैं। उन्होंने कहा कि उनकी वास्तविक ताकत करोड़ों कार्यकर्ता हैं, जो ‘मां, माटी, मानुष’ की विचारधारा में विश्वास रखते हैं।

पार्टी कार्यालय को लेकर चल रहे विवाद पर भी ममता बनर्जी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि तृणमूल भवन किसी व्यक्ति विशेष की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि पूरे संगठन की संपत्ति है। उन्होंने दावा किया कि भवन का किराया नियमित रूप से जमा किया जा रहा है और उससे जुड़े सभी कानूनी दस्तावेज पार्टी के पास सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई इमारत पर कब्जा भी कर ले, तो इससे जनता के दिलों में बसे संगठन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। उनके शब्दों में, “भवनों पर कब्जा किया जा सकता है, लेकिन लोगों के दिलों पर नहीं।”

अपने संबोधन में उन्होंने वरिष्ठ नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे का भी उल्लेख किया। ममता ने कहा कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि काफी समय से कुछ गतिविधियां चल रही थीं, जिनके संकेत पार्टी नेतृत्व को पहले से मिल रहे थे।

स्पेन में दबोचा गया वांटेड गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों: पंजाब पुलिस की खुफिया सूचना पर मैड्रिड में कार्रवाई, भारत लाने की तैयारी तेज

मैड्रिड। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही एक अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई में स्पेन की सुरक्षा एजेंसियों ने वांटेड गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह उर्फ गोल्डी ढिल्लों को राजधानी मैड्रिड में हिरासत में ले लिया है। यह कार्रवाई पंजाब पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) द्वारा साझा की गई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। लंबे समय से फरार चल रहा गोल्डी ढिल्लों हत्या, रंगदारी, संगठित अपराध और अंतरराष्ट्रीय गैंग नेटवर्क से जुड़े कई मामलों में जांच एजेंसियों के रडार पर था। उसकी गिरफ्तारी को सीमा पार सक्रिय गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ चल रहे अभियान में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार भारतीय एजेंसियां काफी समय से गोल्डी ढिल्लों की विदेशों में गतिविधियों पर नजर रखे हुए थीं। उसकी लोकेशन और नेटवर्क से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं लगातार विदेशी सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा की जा रही थीं। इसी समन्वय के परिणामस्वरूप स्पेन की सुरक्षा एजेंसियों ने मैड्रिड में उसे हिरासत में लेने की कार्रवाई की। हालांकि भारतीय अधिकारियों की ओर से अभी तक उसके प्रत्यर्पण अथवा निर्वासन की प्रक्रिया को लेकर औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि भारत सरकार अब राजनयिक और कानूनी माध्यमों से उसे भारत लाने की प्रक्रिया तेज करेगी।

गोल्डी ढिल्लों का नाम कई चर्चित आपराधिक मामलों में सामने आ चुका है। जांच एजेंसियों के अनुसार उसका संबंध चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित एक फार्मेसी में दिनदहाड़े हुई कैशियर की हत्या से जोड़ा गया है। इसके अलावा उस पर आम आदमी पार्टी की विधायक नीना मित्तल को कथित रूप से धमकी देने के आरोप भी हैं। सुरक्षा एजेंसियों का यह भी दावा है कि उसका नाम कनाडा में हुई कई गोलीबारी की घटनाओं और वहां सक्रिय भारतीय मूल के आपराधिक गिरोहों से भी जुड़ा रहा है।

पंजाब पुलिस के अधिकारियों के अनुसार गोल्डी ढिल्लों कभी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह से जुड़ा हुआ था। बाद के वर्षों में दोनों के बीच कथित तौर पर मतभेद बढ़े और उनके संबंध दुश्मनी में बदल गए। इसके बावजूद गोल्डी ढिल्लों ने विदेश में रहकर अपना अलग आपराधिक नेटवर्क विकसित किया और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तथा दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय अपराधियों के साथ संपर्क बनाए रखा। पुलिस का कहना है कि विदेश में बैठकर वह रंगदारी वसूली, आपराधिक साजिशों और गिरोह संचालन जैसी गतिविधियों को कथित रूप से निर्देशित करता रहा।

जांच एजेंसियों के अनुसार गोल्डी ढिल्लों को ‘गोल्डी राजपुरा’ के नाम से भी जाना जाता है। वह कनाडा में बैठे गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार का करीबी सहयोगी माना जाता रहा है। गोल्डी बरार को भारत सरकार आतंकवादी घोषित कर चुकी है और उसका नाम कई हाई-प्रोफाइल आपराधिक मामलों में सामने आ चुका है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि गोल्डी ढिल्लों और गोल्डी बरार दो अलग-अलग व्यक्ति हैं, जिन्हें लेकर कई बार भ्रम की स्थिति बन जाती है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दायर एक चार्जशीट में भी गोल्डी ढिल्लों का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। चंडीगढ़ के सेक्टर-5 के एक कारोबारी से जुड़े रंगदारी और फायरिंग मामले में एनआईए ने गोल्डी बरार के साथ गोल्डी ढिल्लों को भी सह-साजिशकर्ता बताया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि दोनों ने मिलकर संगठित अपराध और रंगदारी के नेटवर्क को संचालित करने की साजिश रची थी। इस मामले में दोनों लंबे समय से फरार चल रहे थे और जांच एजेंसियां उनकी तलाश में जुटी थीं। पंजाब पुलिस के अनुसार गोल्डी ढिल्लों वर्ष 2022 में भारत छोड़कर विदेश भाग गया था। इसके बाद उसने कथित तौर पर विदेश से ही अपने गिरोह का संचालन शुरू कर दिया। जांच में सामने आया कि उसने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय अपराधियों के साथ संपर्क स्थापित कर रंगदारी वसूली, हथियारों की आपूर्ति और अन्य संगठित आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। पुलिस का दावा है कि उसके नेटवर्क में कई शूटर और सहयोगी शामिल थे, जो उसके निर्देशों पर विभिन्न राज्यों में आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे।

एक महत्वपूर्ण मामले में पुलिस ने गोल्डी ढिल्लों के दो कथित गुर्गों को मोहाली और राजपुरा क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान उनके पास से पांच पिस्तौल, बड़ी संख्या में कारतूस तथा नशीली गोलियों का जखीरा बरामद किया गया था। पुलिस का आरोप है कि दोनों किसी हत्या की साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे और उनके तार सीधे गोल्डी ढिल्लों के नेटवर्क से जुड़े हुए थे। इस कार्रवाई के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियों ने उसके अंतरराष्ट्रीय संपर्कों की निगरानी और तेज कर दी थी।

स्कूली किताब में आतंकी को ‘शहीद’ बताए जाने पर जम्मू-कश्मीर में बवाल, सरकार का बड़ा एक्शन; 8 अधिकारी निलंबित, लेखक-प्रकाशक ब्लैकलिस्ट

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के सरकारी स्कूलों में छात्रों को उपलब्ध कराई गई एक पुस्तक की सामग्री को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत पुस्तकालयों और स्कूलों में पहुंचाई गई एक पुस्तक में प्रतिबंधित आतंकी मकबूल भट्ट को ‘शहीद’ तथा कुछ अलगाववादी नेताओं को ‘स्वतंत्रता सेनानी’ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मामला सामने आते ही राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। विवाद बढ़ने के बाद जम्मू-कश्मीर सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के आठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही संबंधित पुस्तकों के लेखक और प्रकाशकों को ब्लैकलिस्ट करने तथा उनकी सभी पुस्तकों को सरकारी स्कूलों और पुस्तकालयों से हटाने का निर्णय लिया गया है। यह मामला सबसे पहले जम्मू-कश्मीर पीपुल्स फोरम (जेकेपीएफ) द्वारा सार्वजनिक किया गया। संगठन ने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूलों में उपलब्ध कराई गई पुस्तकों में इतिहास को तथ्यों के विपरीत प्रस्तुत किया गया है और ऐसी सामग्री शामिल की गई है, जो छात्रों के सामने विवादित ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तियों की भ्रामक तस्वीर पेश करती है।

संगठन का कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य तथ्यपरक और संतुलित जानकारी देना होना चाहिए, न कि ऐसे व्यक्तियों का महिमामंडन करना जिनकी भूमिका को लेकर गंभीर कानूनी और ऐतिहासिक विवाद रहे हैं।

मामला सार्वजनिक होने के बाद जम्मू-कश्मीर की राजनीति भी गर्मा गई। विपक्षी दलों ने सरकार से जवाब मांगा कि ऐसी पुस्तकें सरकारी स्कूलों तक कैसे पहुंचीं और उनकी सामग्री की जांच किस स्तर पर की गई। विपक्ष का कहना है कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था में शामिल किसी भी पुस्तक को पाठ्यक्रम या पुस्तकालयों में शामिल करने से पहले कई स्तरों पर समीक्षा और अनुमोदन की प्रक्रिया होती है। ऐसे में विवादित सामग्री वाली पुस्तक का छात्रों तक पहुंचना केवल एक साधारण प्रशासनिक भूल नहीं माना जा सकता।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने इस पूरे प्रकरण को गंभीर बताते हुए सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी पुस्तक को सरकारी स्कूलों में उपलब्ध कराया गया है, तो यह स्पष्ट है कि वह निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रिया से होकर गुजरी होगी। ऐसे में जिम्मेदारी तय किए बिना केवल औपचारिक कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना ने सरकार की कार्यप्रणाली और उसकी मंशा दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सुनील शर्मा ने कहा कि यदि किसी विवादित पुस्तक को मंजूरी देकर छात्रों तक पहुंचाया गया है, तो यह अत्यंत गंभीर विषय है। उनके अनुसार शिक्षा व्यवस्था में ऐसी सामग्री का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, जो आतंकवाद या अलगाववाद से जुड़े व्यक्तियों का महिमामंडन करती प्रतीत हो। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने, निर्णय प्रक्रिया में शामिल सभी अधिकारियों की भूमिका की समीक्षा करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

विवाद बढ़ने के बाद जम्मू-कश्मीर सरकार ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले को गंभीरता से लिया। सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के आठ अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। प्रारंभिक जांच में इन अधिकारियों की भूमिका पुस्तक के चयन, स्वीकृति अथवा खरीद प्रक्रिया से जुड़ी बताई जा रही है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि मामले की विस्तृत जांच जारी रहेगी और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी।

सरकार ने केवल अधिकारियों पर कार्रवाई तक ही स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि संबंधित पुस्तकों के लेखक और प्रकाशकों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए हैं। उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, जिससे भविष्य में उनके प्रकाशनों की सरकारी खरीद या शैक्षणिक संस्थानों में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही निर्देश जारी किए गए हैं कि उनके सभी प्रकाशनों को केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी स्कूलों और सार्वजनिक पुस्तकालयों से तत्काल हटाया जाए।

इस घटनाक्रम के बाद शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी पुस्तक को स्कूलों तक पहुंचाने से पहले उसकी सामग्री का तथ्यात्मक परीक्षण, शैक्षणिक मूल्यांकन और वैचारिक संतुलन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होता है। यदि इस प्रक्रिया में कहीं लापरवाही हुई है, तो उसकी जवाबदेही तय करना जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सामाजिक संगठनों ने भी मांग की है कि छात्रों को उपलब्ध कराई जाने वाली सभी पुस्तकों की व्यापक समीक्षा की जाए। उनका कहना है कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था में शामिल सामग्री पूरी तरह तथ्यपरक, निष्पक्ष और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप होनी चाहिए। इतिहास, राजनीति और समाज से जुड़े विषयों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि इनका सीधा प्रभाव छात्रों की समझ और दृष्टिकोण पर पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में शिक्षा संबंधी सामग्री का चयन और भी अधिक जिम्मेदारी का विषय है। यहां पाठ्य सामग्री केवल अकादमिक महत्व ही नहीं रखती, बल्कि सामाजिक सद्भाव, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता से भी जुड़ी होती है।

बांकीपुर उपचुनाव बना राष्ट्रीय सियासत का रणक्षेत्र: बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर, प्रशांत किशोर की एंट्री से मुकाबला हुआ बेहद दिलचस्प

पटना। बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे अधिक चर्चा पटना की हाई-प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट की हो रही है। सामान्य तौर पर एक विधानसभा उपचुनाव स्थानीय राजनीतिक समीकरणों तक सीमित माना जाता है, लेकिन इस बार बांकीपुर का चुनाव राज्य की सीमाओं से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद यह सीट रिक्त हुई है, जिस पर 30 जुलाई को मतदान होना है। इस चुनाव को केवल एक विधायक के चयन के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे भाजपा की राजनीतिक पकड़, संगठनात्मक ताकत और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की प्रतिष्ठा की परीक्षा के रूप में भी माना जा रहा है।

बांकीपुर लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। पिछले तीन दशक से इस सीट पर भाजपा का लगातार कब्जा रहा है और पार्टी ने यहां मजबूत सामाजिक व राजनीतिक आधार तैयार किया है। ऐसे में इस सीट को बचाए रखना भाजपा के लिए केवल चुनावी जीत का प्रश्न नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक साख बनाए रखने का भी मामला बन गया है। दूसरी ओर विपक्ष भी इस अवसर को भाजपा के अभेद्य किले में सेंध लगाने के रूप में देख रहा है, जिससे मुकाबला पहले से कहीं अधिक रोचक और चुनौतीपूर्ण बन गया है।

उपचुनाव की घोषणा के साथ ही भाजपा ने संगठनात्मक स्तर पर पूरी सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें आयोजित की जा रही हैं। हालांकि पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन टिकट के दावेदारों की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। पार्टी नेतृत्व ऐसे चेहरे की तलाश में जुटा है जो न केवल स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ रखता हो, बल्कि नितिन नवीन की राजनीतिक विरासत को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सके।

भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह सीट सीधे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ी हुई है। यदि पार्टी यहां जीत दर्ज करती है तो यह संदेश जाएगा कि नितिन नवीन का प्रभाव और भाजपा का जनाधार अब भी कायम है। लेकिन यदि परिणाम उम्मीद के विपरीत आते हैं, तो विपक्ष इसे भाजपा की राजनीतिक कमजोरी और संगठनात्मक चुनौती के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करेगा। यही कारण है कि पार्टी इस चुनाव को पूरी गंभीरता से ले रही है।

इस बीच जन सुराज अभियान के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। सूत्रों के अनुसार प्रशांत किशोर स्वयं बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। बताया जा रहा है कि वह 11 जुलाई को अपना नामांकन दाखिल करेंगे और जन सुराज की ओर से उम्मीदवार होंगे। इसकी औपचारिक घोषणा किए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो यह चुनाव सीधे भाजपा और प्रशांत किशोर के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई में बदल सकता है।

प्रशांत किशोर की संभावित उम्मीदवारी को राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वर्षों तक देश के कई बड़े राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति तैयार करने वाले प्रशांत किशोर अब अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटे हैं। बिहार में जन सुराज के माध्यम से वह स्वयं को एक वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे में भाजपा के सबसे मजबूत माने जाने वाले क्षेत्र से चुनाव लड़ने का निर्णय उनकी राजनीतिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। यदि वह इस सीट पर मजबूत प्रदर्शन करते हैं तो इससे उनकी पार्टी को राज्यव्यापी राजनीतिक पहचान मिल सकती है।

दूसरी ओर महागठबंधन भी इस सीट को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की ओर से भी उम्मीदवार उतारने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी तक महागठबंधन ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विपक्ष पूरी ताकत के साथ भाजपा को चुनौती देने की कोशिश करेगा। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

बांकीपुर विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास भी इसे विशेष महत्व प्रदान करता है। यह क्षेत्र पहले पटना पश्चिम विधानसभा के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद इसका नाम बदलकर बांकीपुर विधानसभा कर दिया गया। यह क्षेत्र लंबे समय से भाजपा के प्रभाव वाले इलाकों में गिना जाता है और शहरी मतदाताओं की बड़ी संख्या यहां चुनावी परिणामों को प्रभावित करती रही है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का इस सीट से गहरा पारिवारिक और राजनीतिक संबंध रहा है। उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा ने वर्ष 1995 में तत्कालीन पटना पश्चिम विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बनकर भाजपा की मजबूत नींव रखी थी। इसके बाद इस क्षेत्र में भाजपा का जनाधार लगातार मजबूत होता गया। वर्ष 2005 में नवीन किशोर सिन्हा के निधन के बाद राजनीति की जिम्मेदारी उनके पुत्र नितिन नवीन ने संभाली। वर्ष 2006 के उपचुनाव में उन्होंने पहली बार जीत दर्ज की और इसके बाद लगातार चुनाव जीतते हुए इस सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नितिन नवीन का पूरा राजनीतिक सफर इसी सीट से जुड़ा रहा है। एक उपचुनाव से विधायक बनने वाले नितिन नवीन आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंचे हैं। अब उनके राज्यसभा जाने के बाद उसी सीट पर फिर उपचुनाव हो रहा है। इस वजह से यह चुनाव उनके राजनीतिक प्रभाव और जनाधार की भी परीक्षा माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस चुनाव में स्थानीय मुद्दों के साथ-साथ राजनीतिक संदेश भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भाजपा विकास कार्यों, संगठन की मजबूती और अपने पारंपरिक मतदाताओं पर भरोसा कर रही है, जबकि विपक्ष सत्ता विरोधी माहौल, स्थानीय असंतोष और नए राजनीतिक समीकरणों के जरिए मुकाबले को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगा। वहीं यदि प्रशांत किशोर मैदान में उतरते हैं तो युवा मतदाताओं और बदलाव की राजनीति को लेकर भी चुनावी बहस तेज होने की संभावना है।

बांकीपुर सीट की सामाजिक संरचना भी चुनाव को रोचक बनाती है। यहां मध्यम वर्ग, व्यापारी समुदाय, सरकारी कर्मचारी, शिक्षित मतदाता, युवा और पारंपरिक शहरी वोटर बड़ी संख्या में हैं।

संपादकीय

जानलेवा मैनहोल

मानसून की बारिश जहां किसानों के लिये राहत लेकर आती हैं, वहीं तंत्र की काहिली और भ्रष्टाचार की पोल भी खोल देती है। मानसून की शुरुआती बारिश ने एक बार फिर सार्वजनिक संरचनाओं की जानलेवा खामियों को ही उजागर किया। मुंबई में बारिश के पानी में नजर न आने वाले एक खुले मैनहोल में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं हाल ही में खुले बहुचर्चित दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे ने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली उजागर कर दी। ये घटनाएं हमें बताती हैं कि बारिश के मौसम में स्थानीय निकायों की लापरवाही व खराब इंजीनियरिंग के चलते कैसे लोगों का जीवन जोखिम में पड़ जाता है। निस्संदेह, मुंबई में हुए हादसे को रोका जा सकता था। कथित साफ-सफाई के बाद लापरवाही से खुला छोड़ा गया मैनहोल तब जानलेवा बन गया, जब बारिश के पानी से ढका खुला मैनहोल नजर नहीं आया। निस्संदेह, दुर्घटना के बाद अधिकारियों को निलंबित करना और ठेकेदार को काली सूची में डालना, फौरी तौर पर सही कदम है, लेकिन सवाल यह है कि हादसे होने के बाद ही ऐसे कदम क्यों उठाये जाते हैं? पहले से ही नागरिकों की सुरक्षा के लिये चाक-चौबंद व्यवस्था क्यों नहीं होती? कायदे से किसी सड़क पर मैनहोल खोलने से पहले बैरिकेड्स लगाने, चेतावनी देने वाले संकेत और अस्थायी कवर से ढकना बुनियादी सुरक्षा उपाय हैं। जिन्हें अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बीते साल भी दिल्ली में भारी बारिश के दौरान स्कूटर फिसलने से एक महिला और उसका तीन साल का बेटा पानी से भरे नाले में बह गये थे। ये असुरक्षित ड्रेनेज संरचना की घातकता को ही दर्शाता है। विडंबना है कि हमारा तंत्र सालभर सोया रहता है और जब बरसात शुरू होने को होती है, तब मरम्मत- नालों की सफाई के काम की औपचारिकता पूरी करता है। निस्संदेह, संबंधित विभागों के अधिकारियों की सर्वकालिक जवाबदेही तय की जानी चाहिए। फिर किसी भी तरह की लापरवाही होने पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

वहीं दूसरी ओर दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के धंसने की घटना भी एक चिंताजनक स्थिति को दर्शाती है। यह निर्विवाद सत्य है कि कोई सड़क बारिश आने के कारण रातों-रात नहीं धंसती है। इसमें सड़क निर्माण के दौरान सतर्कता की अनदेखी भी शामिल है। दरअसल, सड़क निर्माण के दौरान जल निकासी की कारगर व्यवस्था न होने, मिट्टी की स्थिरता सुनिश्चित न करने और निर्माण में गुणवत्ता की कमी से ही बरसाती पानी सड़क की सतह के नीचे मिट्टी को धीरे-धीरे काटने लगता है। कालांतर यह मिट्टी का कटाव ही सड़क धंसने की वजह बन जाता है। साल 2024 में बिहार में पुलों के ढहने की श्रृंखला ने भी निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के उपयोग की हकीकत बतायी थी। इसी तरह की चिंताएं अकसर सामने आती हैं जब आधुनिक कहे जाने वाले महानगरों बेंगलुरू और मुंबई में हर मानसून में सड़कों में बने गड्ढे दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। इतना ही नहीं इससे यातायात में भी अराजकता व व्यवधान पैदा होता है। बहरहाल, इन सभी घटनाओं के मूल में एक बात तो समान है कि स्थानीय निकाय व प्रशासन जोखिमों का समय रहते अनुमान नहीं लगा पाते हैं। यह तथ्य सभी अधिकारी जानते हैं कि एक निश्चित समय पर मानसून आता है। बाकायदा समय-समय पर सूचना माध्यमों में मौसम विभाग द्वारा मानसून की भविष्यवाणी की जाती है। लेकिन अधिकारी तब जागते हैं जब स्थितियां जटिल हो जाती हैं। वे इन हालातों को अप्रत्याशित आपात स्थिति के रूप में दर्शाने का प्रयास करते हैं। दरअसल,कई स्तरों पर होने वाली कमीशनखोरी व राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते अकसर ठेकेदारों की जवाबदेही तय नहीं की जाती है। विडंबना यह भी है कि निरीक्षण भी अक्सर खानापूर्ति जैसा ही होता है। वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक संरचना का रखरखाव भी निवारक के बजाय प्रतिक्रियात्मक ही रहता है। वास्तव में कारगर समाधान के लिये जरूरी है कि मानसून से पहले सुरक्षा उपायों को संस्थागत ढंग से सुनिश्चित किया जाए, इंजीनियरिंग मानकों को सख्ती से लागू किया जाए, गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच हो और ठेकेदार को कानूनी रूप से जवाबदेह बनाया जाए। दुर्घटना होने के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय यह सुनिश्चित हो कि ऐसी घटनाएं हो ही न पाएं।

क्या नितिन गडकरी की E20 नीति की वजह से खराब हो रही हैं गाड़ियां?

"हम आपको बता दें कि ई20 यानी पेट्रोल में 20 प्रतिशत तक एथनॉल मिश्रण को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। ताजा मामले में बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने अपनी टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस में आई खराबी का आरोप सीधे ई20 पेट्रोल और सरकार की नीति पर लगाया है।"

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पर इन दिनों चौतरफा हमले हो रहे हैं। कभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ई20 पेट्रोल को वाहनों की खराबी का कारण बताया जा रहा है, तो कभी सड़कों पर उतरने की चेतावनी देकर केंद्र सरकार की एथनॉल नीति के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जो लंबे समय से एथनॉल मिश्रित ईंधन को भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और किसानों की आय बढ़ाने का माध्यम बताते रहे हैं, अब उसी नीति को लेकर गंभीर सवालों के घेरे में हैं। हम आपको बता दें कि ई20 यानी पेट्रोल में 20 प्रतिशत तक एथनॉल मिश्रण को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। ताजा मामले में बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने अपनी टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस में आई खराबी का आरोप सीधे ई20 पेट्रोल और सरकार की नीति पर लगाया है। मनीष का दावा है कि उनकी दो महीने पुरानी और लगभग 12 हजार किलोमीटर चली गाड़ी का इंजन अचानक खराब हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि फ्यूल टैंक से निकाले गए पेट्रोल में 20 प्रतिशत से अधिक एथनॉल और अशुद्धियां मिलीं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वह काफी भावुक नजर आए और बोले कि लाखों रुपये खर्च कर खरीदी गई गाड़ी इतनी जल्दी खराब हो जाना गंभीर चिंता का विषय है।

देखा जाये तो मनीष कश्यप अकेले नहीं हैं। देशभर में हजारों वाहन मालिक माइलेज घटने, इंजन परफॉर्मेंस कम होने और वाहनों में तकनीकी समस्याओं की शिकायत कर रहे हैं। कई वीडियो में गुलाबी रंग का पेट्रोल, टंकी में पानी जैसी परत और अन्य अशुद्धियां दिखाकर दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल में एथनॉल की मात्रा तय सीमा से अधिक है। हालांकि सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय इन दावों को खारिज कर रहे हैं।

इस विवाद ने अब राजनीतिक और सामाजिक रूप भी ले लिया है। राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने दिल्ली के जंतर मंतर पर ई20 नीति के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। "टीम भारत अगेंस्ट द एथनॉल स्कैम" के बैनर तले प्रस्तावित इस प्रदर्शन को एथनॉल नीति के खिलाफ पहला बड़ा सार्वजनिक आंदोलन बताया जा रहा है। पूनावाला का कहना है कि लोग एथनॉल नीति के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि इसकी जल्दबाजी में की गई क्रियान्वयन प्रक्रिया और उपभोक्ताओं को विकल्प न दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली तो कुछ लोग नितिन गडकरी के आवास के बाहर धरने पर बैठ सकते हैं।

देखा जाये तो विवाद केवल वाहन खराबी तक सीमित नहीं है। एक उद्योगपति ने भी सरकार की ई20 नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में हुई सुनवाई का हवाला देते हुए कहा कि सरकार जनता के सामने इस योजना को पूरी तरह सफल बता रही है, लेकिन अदालत में इसे अभी भी "चल रहा प्रयोग" बताया गया। हालांकि बाद में अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने इस दावे को गलत बताया। वहीं उक्त उद्योगपति का कहना है कि असली चिंता उन उद्योगों और निवेशकों की है जिन्होंने सरकार की नीति पर भरोसा करके एथनॉल संयंत्रों में अरबों रुपये का निवेश किया। यदि एथनॉल की खरीद और मांग ही निश्चित नहीं है, तो निवेशकों को किस भरोसे निवेश के लिए प्रेरित किया गया।

हम आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड और कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश से जुड़ा था, जिसमें एथनॉल आवंटन प्रक्रिया को दोबारा खोलने की बात कही गई थी। इस सुनवाई के दौरान यह भी सवाल उठा कि सरकार द्वारा एथनॉल खरीद की बाध्यता वास्तव में कितनी मजबूत है। आलोचकों का कहना है कि यदि खरीद केवल "सर्वश्रेष्ठ प्रयास" के आधार पर होगी तो उद्योगों की वित्तीय स्थिरता पर खतरा पैदा हो सकता है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने एथनॉल नीति के आर्थिक और कृषि प्रभावों पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ई20 कार्यक्रम भारत को विदेशी मक्के और उससे बने उत्पादों पर अधिक निर्भर बना सकता है। सोशल मीडिया यूजर्स ने यह भी आरोप लगाया है कि यह नीति अब किसान केंद्रित कम और आयात आधारित ढांचे जैसी अधिक दिखाई देने लगी है। उन्होंने सरकार से ई20 की अनिवार्यता पर पुनर्विचार कर ई5 या ई10 जैसे विकल्प फिर से उपलब्ध कराने की मांग की है।

वहीं देशी और विदेशी वाहन निर्माता कंपनियों ने ई20 पेट्रोल को लेकर मिश्रित लेकिन संतुलित रुख अपनाया है। मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टोयोटा, होंडा और किआ जैसी कंपनियों ने कहा है कि अप्रैल 2023 के बाद बने अधिकांश नए वाहन ई20 अनुकूल बनाए जा चुके हैं और उनमें इस ईंधन के इस्तेमाल से कोई बड़ा सुरक्षा खतरा नहीं है। वाहन उद्योग संगठन सियाम ने भी माना है कि ई20 से माइलेज में लगभग 2 से 4 प्रतिशत तक गिरावट आ सकती है, लेकिन इससे स्थायी इंजन क्षति का कोई प्रमाण नहीं मिला है। वहीं महिंद्रा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्वीकार किया कि ई20 सुरक्षित तो है, लेकिन इससे परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ सकता है। टोयोटा सहित कई कंपनियों ने अपने नए पेट्रोल मॉडलों को ई20 अनुकूल घोषित किया है, जबकि कुछ विशेषज्ञों और कंपनियों ने पुराने वाहनों में सावधानी बरतने की सलाह दी है।

दूसरी ओर केंद्र सरकार लगातार इस योजना का बचाव कर रही है। सरकार का दावा है कि भारत ने निर्धारित समय से पहले दिसंबर 2025 में पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार इस कार्यक्रम से देश को 1.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा बचत हुई, किसानों को 1.60 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारी कमी आई। सरकार का कहना है कि इससे 310 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चे तेल का विकल्प तैयार हुआ। सरकार का यह भी कहना है कि वाहन कंपनियों और सियाम के साथ व्यापक चर्चा के बाद ही ई20 लागू किया गया और कई निर्माता वर्ष 2009 से ही ई20 अनुकूल इंजन विकसित कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी माइलेज घटने के दावों को मामूली बताया है। उनका कहना है कि एथनॉल मिश्रित ईंधन से इंजन की नॉकिंग कम होती है और वाहन की गति क्षमता बेहतर होती है। वहीं नितिन गडकरी ने एथनॉल विरोधी प्रचार को "पेड कैंपेन" करार दिया है। उनका आरोप है कि पेट्रोलियम लॉबी भारत की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होने से परेशान है और इसलिए दुष्प्रचार कर रही है। गडकरी ने यह चुनौती भी दी कि दुनिया में कोई एक उदाहरण दिखाया जाए जहां ई20 पेट्रोल से वाहन स्थायी रूप से खराब हुए हों।

बहरहाल, फिलहाल एथनॉल मिश्रित पेट्रोल पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। एक ओर सरकार इसे किसानों, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए क्रांतिकारी कदम बता रही है, तो दूसरी ओर उपभोक्ता, वाहन मालिक और कुछ उद्योग विशेषज्ञ इसके प्रभावों को लेकर गंभीर चिंता जता रहे हैं। आने वाले समय में यह बहस केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सड़कों, अदालतों और राजनीतिक मंचों तक और तेज होती दिखाई दे सकती है।

प्रेरणा

अटूट संकल्प और ज्ञान की प्यास ने सोफी जर्मेन को बनाया गणित की अमर विभूति

इतिहास इस बात का साक्षी है कि असाधारण उपलब्धियाँ केवल प्रतिभा के बल पर नहीं मिलतीं, बल्कि उनके पीछे अटूट संकल्प, अथक परिश्रम, विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करने का साहस और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग विश्वास छिपा होता है। संसार में ऐसे अनेक महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने सामाजिक बंधनों, आर्थिक कठिनाइयों और भेदभावपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद अपनी प्रतिभा के बल पर नया इतिहास रचा। इन्हीं प्रेरणादायी व्यक्तित्वों में फ्रांस की महान गणितज्ञ सोफी जर्मेन का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने ऐसे समय में गणित के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई, जब महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करना तो दूर, गणित जैसे विषय का अध्ययन करना भी समाज की दृष्टि में अनुचित माना जाता था। लेकिन सोफी ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि मनुष्य के भीतर सीखने की सच्ची लगन और दृढ़ संकल्प हो, तो कोई भी सामाजिक बंधन उसकी उड़ान को रोक नहीं सकता।

अठारहवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में फ्रांस राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा था। फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे देश का वातावरण बदल दिया था। चारों ओर अस्थिरता, संघर्ष और भय का माहौल था। ऐसे समय में अधिकांश बच्चे घरों में ही रहने को विवश थे। इन्हीं परिस्थितियों में पेरिस के एक समृद्ध परिवार में जन्मी सोफी जर्मेन ने अपने जीवन की दिशा बदल देने वाला निर्णय लिया। जब वे लगभग तेरह वर्ष की थीं, तब बाहर की अशांत परिस्थितियों के कारण अधिकतर समय घर के भीतर ही बिताती थीं। समय व्यतीत करने के लिए उन्होंने अपने पिता की विशाल लाइब्रेरी में रखी पुस्तकों को पढ़ना प्रारंभ किया। शुरुआत में उनका उद्देश्य केवल समय बिताना था, लेकिन जल्द ही गणित की पुस्तकों ने उनके मन को पूरी तरह आकर्षित कर लिया।

गणित के कठिन सिद्धांत, जटिल समीकरण और तार्किक प्रश्न उन्हें किसी रहस्यमयी संसार की तरह दिखाई देते थे। जितना अधिक वे पढ़तीं, उतनी ही उनकी जिज्ञासा बढ़ती जाती। उन्होंने स्वयं अध्ययन करके ऐसे प्रश्न हल करने शुरू कर दिए, जिन्हें उस समय बड़े-बड़े विद्यार्थी भी कठिन मानते थे। बिना किसी औपचारिक मार्गदर्शन के उन्होंने गणित के सिद्धांतों को समझना प्रारंभ किया और धीरे-धीरे उनकी प्रतिभा निखरती चली गई। यह उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता का प्रमाण था कि वे कठिन समस्याओं के समाधान स्वयं खोज लेती थीं।

लेकिन उस समय का समाज महिलाओं के लिए इतना उदार नहीं था। अठारहवीं शताब्दी में यूरोप के अधिकांश देशों में महिलाओं की शिक्षा सीमित थी। विशेष रूप से गणित, विज्ञान और दर्शन जैसे विषय केवल पुरुषों के लिए उपयुक्त माने जाते थे। लोगों का मानना था कि महिलाओं को घर-परिवार तक ही सीमित रहना चाहिए। ऐसे वातावरण में किसी लड़की का गणितज्ञ बनने का सपना लगभग असंभव माना जाता था। सोफी को भी अनेक सामाजिक बाधाओं और विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को त्यागने के बजाय उन्हें और मजबूत बना लिया।

इसी बीच पेरिस में प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान 'इकोले पोलिटेक्निक' की स्थापना हुई। यह संस्थान गणित, विज्ञान और इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा के लिए जाना जाता था। सोफी वहाँ पढ़ना चाहती थीं, लेकिन महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। यह किसी भी प्रतिभाशाली छात्रा के लिए निराशाजनक स्थिति थी। अधिकांश लोग शायद यहीं हार मान लेते, लेकिन सोफी ने हार स्वीकार नहीं की। उन्होंने एक ऐसा उपाय खोजा जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी।

सोफी ने 'मोंसियूर ले ब्लांक' नामक एक काल्पनिक पुरुष छात्र का नाम अपनाया। इसी नाम से उन्होंने अपने गणितीय नोट्स, शोधपत्र और समस्याओं के समाधान इकोले पोलिटेक्निक के प्राध्यापकों को भेजने शुरू किए। उनके लेखन में इतनी स्पष्टता, तर्कशक्ति और मौलिकता थी कि संस्थान के विद्वान गणितज्ञ भी अत्यंत प्रभावित हुए। किसी को यह कल्पना भी नहीं थी कि इतने उच्च स्तर का कार्य किसी युवा महिला द्वारा किया जा रहा है।

उनके कार्य से सबसे अधिक प्रभावित महान गणितज्ञ जोसेफ-लुई लांग्रेज हुए। उन्होंने 'मोंसियूर ले ब्लांक' नामक इस प्रतिभाशाली छात्र से मिलने की इच्छा व्यक्त की। जब वास्तविकता सामने आई और उन्हें ज्ञात हुआ कि यह असाधारण प्रतिभा किसी पुरुष की नहीं, बल्कि एक युवा महिला सोफी जर्मेन की है, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उस समय समाज में महिलाओं के प्रति प्रचलित धारणाओं के बीच यह एक अभूतपूर्व घटना थी। लांग्रेज ने न केवल सोफी की प्रतिभा का सम्मान किया, बल्कि उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया और आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रोत्साहन दिया। यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ।

गुरु का मार्गदर्शन मिलने के बाद सोफी ने गणित के अनेक जटिल क्षेत्रों में गहन शोध प्रारंभ किया। विशेष रूप से संख्या सिद्धांत (Number Theory) में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने महान गणितज्ञ पियरे द फर्माट द्वारा प्रस्तुत प्रसिद्ध फर्माट का अंतिम प्रमेय (Fermat's Last Theorem) को सिद्ध करने की दिशा में एक मौलिक और प्रभावशाली योजना विकसित की। यद्यपि यह प्रमेय उनके जीवनकाल में पूर्णतः सिद्ध नहीं हो सका, फिर भी उनके द्वारा विकसित सिद्धांतों और विधियों ने बाद के गणितज्ञों के लिए मजबूत आधार तैयार किया। आज भी संख्या सिद्धांत में "सोफी जर्मेन अभाज्य संख्याएँ" (Sophie Germain Primes) उनके नाम पर जानी जाती हैं, जो उनके स्थायी योगदान का प्रमाण हैं।

सोफी जर्मेन ने केवल संख्या सिद्धांत तक ही स्वयं को सीमित नहीं रखा। उन्होंने भौतिकी और प्रत्यास्थता (Elasticity Theory) के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शोध किए। उन्होंने यह समझने का प्रयास किया कि विभिन्न प्रकार की धातु की प्लेटें कंपन करने पर किस प्रकार व्यवहार करती हैं। उनके शोध ने आगे चलकर इंजीनियरिंग, वास्तुकला और आधुनिक भौतिकी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उस युग में किसी महिला वैज्ञानिक के लिए अत्यंत बड़ी उपलब्धि थी।

उनकी असाधारण उपलब्धियों को देखते हुए पेरिस विज्ञान अकादमी ने उन्हें अपने प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली वे पहली महिला बनीं। उस समय यह सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं था, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा था जिन्हें समाज ने शिक्षा और विज्ञान से दूर रखने का प्रयास किया था। सोफी की सफलता ने यह संदेश दिया कि प्रतिभा का कोई लिंग नहीं होता और ज्ञान किसी विशेष वर्ग की संपत्ति नहीं है। सोफी जर्मेन का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि कठिन परिस्थितियाँ अक्सर महान व्यक्तित्वों का निर्माण करती हैं।

पर्यावरण नहीं, अस्तित्व का प्रश्न है वनों का संरक्षण

भारतीय संस्कृति में प्रकृति को सदैव पूजनीय माना गया है। हमारे पर्व और उत्सव केवल सामाजिक उल्लास के अवसर नहीं रहे बल्कि प्रकृति और मानव के सह-अस्तित्व के प्रतीक भी रहे हैं। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के क्षरण, प्रदूषण और जल संकट जैसी अभूतपूर्व चुनौतियों से जूझ रही है, तब भारत में 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाने वाला 'वन महोत्सव' केवल वृक्षारोपण का अभियान नहीं है बल्कि पृथ्वी पर जीवन बचाने का राष्ट्रीय संकल्प बन चुका है। वास्तव में यदि वर्तमान समय की आवश्यकताओं को देखा जाए तो वन महोत्सव से बड़ा कोई उत्सव नहीं हो सकता क्योंकि इसका संबंध केवल पर्यावरण से नहीं बल्कि मानव सभ्यता के भविष्य से है। भारतीय परंपरा में वनों को देवतुल्य माना गया है। वे केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि पृथ्वी के फेफड़े, जैव विविधता के सबसे बड़े आश्रय, नदियों के संरक्षक, जलवायु संतुलन के प्रहरी तथा करोड़ों लोगों की आजीविका के आधार हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से ठीक पहले जुलाई 1947 में दिल्ली में चलाए गए व्यापक वृक्षारोपण अभियान ने वन महोत्सव की अवधारणा को जन्म दिया था, जिसे वर्ष 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। जुलाई के प्रथम सप्ताह का चयन इसलिए किया गया क्योंकि दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान मिट्टी में पर्याप्त नमी होने से पौधों के जीवित रहने की संभावना सर्वाधिक रहती है। आज यह अभियान भारत के 'वसुधैव कुटुम्बकम' के दर्शन का जीवंत प्रतीक बन चुका है। वनों की स्थिति विश्व स्तर पर चिंताजनक बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, पृथ्वी का केवल लगभग 31 प्रतिशत भूभाग ही वनाच्छादित है जबकि प्रतिवर्ष लाखों हेक्टेयर वन क्षेत्र अवैध कटाई, औद्योगीकरण, खनन और अवसंरचनात्मक विकास की भेंट चढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो आगामी दशकों में विश्व के अनेक वर्षावन गंभीर संकट में पड़ सकते हैं। ऐसे समय में भारत जैसे विशाल और जैव विविधता से समृद्ध देश की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। भारत ने हाल के वर्षों में वन संरक्षण और वृक्षारोपण की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण की भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) के अनुसार, देश का कुल वन एवं वृक्ष आवरण बढ़कर 8,27,357 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17 प्रतिशत है। इसमें 7,15,343 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र तथा 1,12,014 वर्ग किलोमीटर वृक्ष आवरण शामिल है। पिछले आकलन की तुलना में कुल हरित आवरण में 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है जबकि अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ उसके बाद आते हैं। वहीं वन घनत्व के अनुपात में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय अग्रणी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट में भारत को कुल वन क्षेत्र के आधार पर विश्व में नौवां स्थान तथा वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में अग्रणी देशों में स्थान प्राप्त हुआ है। हालांकि इन उपलब्धियों के साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि हरित आवरण में हुई वृद्धि का बड़ा हिस्सा प्राकृतिक सघन वनों के बजाय खुले वनों तथा व्यावसायिक वृक्षारोपण के कारण हुआ है। प्राकृतिक वन केवल पेड़ों का समूह नहीं होते बल्कि हजारों वनस्पतियों, जीव-जंतुओं, सूक्ष्मजीवों और जल स्रोतों का जटिल पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। इनका स्थान कृत्रिम पौधारोपण कभी नहीं ले सकता। विशेष चिंता का विषय पूर्वोत्तर भारत है, जहां सड़क निर्माण, जलविद्युत परियोजनाओं, झूम खेती, भूस्खलन तथा अन्य विकास गतिविधियों के कारण कई क्षेत्रों में वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है। अपनी पुस्तक 'प्रदूषण मुक्त सांसें' में मैंने विस्तार से यह स्पष्ट किया है कि वनों के क्षरण का प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रहता बल्कि इसका सीधा असर वन्यजीवों और मानव जीवन पर पड़ता है। प्राकृतिक आवास नष्ट होने से हाथी, बाघ, तेंदुए और अन्य वन्यजीव भोजन एवं पानी की तलाश में मानव बस्तियों की ओर आने लगे हैं, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। दूसरी ओर विकास परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई के बाद प्रतिपूरक वृक्षारोपण तो किया जाता है लेकिन पौधों की देखभाल, सिंचाई और संरक्षण की अनदेखी के कारण उनमें से अधिकांश जीवित नहीं रह पाते। केवल पौधे लगा देना पर्याप्त नहीं है बल्कि उन्हें वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखना ही वास्तविक सफलता है।

आज वन मानव स्वास्थ्य के सबसे बड़े संरक्षक बन चुके हैं। वायु प्रदूषण, जल संकट और भूमि के मरुस्थलीकरण जैसी समस्याओं का सबसे प्रभावी और किफायती समाधान वृक्ष ही हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर जलवायु परिवर्तन की गति को धीमा करते हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं, वर्षा चक्र को संतुलित रखते हैं, भूजल स्तर बनाए रखते हैं तथा मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। बढ़ते प्रदूषण के कारण कैंसर, हृदय रोग, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों से संबंधित बीमारियों में तेजी से वृद्धि हो रही है। साथ ही, अनियमित मानसून, भीषण हीटवेव, सूखा, क्लाउडबर्स्ट और जंगलों में आग जैसी घटनाएं स्पष्ट संकेत हैं कि प्रकृति का संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है। इस संकट से निपटने के लिए भारत ने वर्ष 2030 तक अतिरिक्त 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन सिंक विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें वनों की भूमिका निर्णायक होगी।

बहरहाल, वन महोत्सव का वास्तविक संदेश केवल एक सप्ताह भर लाखों पौधे लगाने तक सीमित नहीं है बल्कि इसकी सफलता इस बात में निहित है कि स्थानीय जलवायु के अनुरूप नीम, पीपल, बरगद, बेल, जामुन, अर्जुन और अन्य देशज प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाए तथा प्रत्येक पौधे की कम से कम तीन वर्षों तक नियमित देखभाल सुनिश्चित की जाए। जब तक वृक्षारोपण को जनभागीदारी और जन-जिम्मेदारी का अभियान नहीं बनाया जाएगा, तब तक हरित भारत का सपना अधूरा रहेगा। विकास और पर्यावरण परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं। आर्थिक प्रगति, आधुनिक तकनीक और अवसंरचनात्मक विकास आवश्यक हैं किंतु वे स्वच्छ वायु, शुद्ध जल और संतुलित जलवायु का विकल्प नहीं बन सकते।

अभियान

धन की देवी मां लक्ष्मी कब करती हैं किसी घर में स्थायी निवास? जानिए 'चंचला' स्वरूप का आध्यात्मिक और शास्त्रीय रहस्य

सनातन धर्म में मां लक्ष्मी को केवल धन और वैभव की देवी नहीं माना गया है, बल्कि वे समृद्धि, सौभाग्य, शुद्धता, ऐश्वर्य, अन्न, सुख, शांति और जीवन की सकारात्मक ऊर्जा की अधिष्ठात्री शक्ति हैं। प्रत्येक गृहस्थ की यही कामना होती है कि उसके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास हो, परिवार आर्थिक रूप से संपन्न रहे और जीवन में कभी अभाव का सामना न करना पड़े। यही कारण है कि दीपावली, कोजागरी पूर्णिमा, शुक्रवार और अन्य शुभ अवसरों पर मां लक्ष्मी की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। लेकिन धार्मिक ग्रंथों में एक रोचक तथ्य मिलता है कि मां लक्ष्मी का एक प्रमुख नाम 'चंचला' भी है। पहली दृष्टि में यह नाम आश्चर्य उत्पन्न करता है, क्योंकि जो देवी समृद्धि प्रदान करती हैं, उन्हें चंचला अर्थात् अस्थिर या गतिशील क्यों कहा गया? क्या वास्तव में मां लक्ष्मी किसी स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहतीं, या फिर इस नाम के पीछे कोई गहन आध्यात्मिक संकेत छिपा हुआ है? शास्त्रों, पुराणों और वैदिक परंपराओं में इसका उत्तर अत्यंत गूढ़ और प्रेरणादायक रूप में मिलता है।

संस्कृत में 'चंचला' शब्द का अर्थ है—जो निरंतर गतिशील हो, जो एक स्थान पर स्थिर न रहे और जो परिस्थितियों के अनुसार अपना स्थान बदलती रहे। यह नाम मां लक्ष्मी के स्वभाव का नहीं, बल्कि धन और भौतिक समृद्धि के स्वभाव का प्रतीक है। संसार में धन कभी स्थायी नहीं रहता। इतिहास इस बात का साक्षी है कि अनेक समृद्ध साम्राज्य समय के साथ समाप्त हो गए और अनेक साधारण परिवार अपनी मेहनत और सदाचार के बल पर समृद्ध बन गए। यही परिवर्तनशीलता लक्ष्मी के चंचला स्वरूप का वास्तविक संदेश है। यह नाम मनुष्य को सावधान करता है कि धन पर कभी अहंकार न करें, क्योंकि यदि उसका सदुपयोग न किया जाए तो वह किसी भी समय साथ छोड़ सकता है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां लक्ष्मी उस स्थान पर अधिक समय तक निवास करती हैं, जहां स्वच्छता, सत्य, परिश्रम, अनुशासन, विनम्रता और धर्म का पालन होता है। इसके विपरीत जहां आलस्य, असत्य, छल-कपट, अपमान, कलह, नशा, क्रोध और अन्याय का वातावरण होता है, वहां लक्ष्मी धीरे-धीरे अपना निवास छोड़ देती हैं। इसीलिए शास्त्रों में केवल लक्ष्मी पूजन का ही महत्व नहीं बताया गया, बल्कि ऐसे आचरण अपनाने पर भी बल दिया गया है जो लक्ष्मी को प्रिय हैं।

समुद्र मंथन की पौराणिक कथा मां लक्ष्मी के स्वरूप को समझने का सबसे महत्वपूर्ण आधार मानी जाती है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीरसागर का मंथन किया, तब चौदह दिव्य रत्न प्रकट हुए। इन्हीं रत्नों में से एक थीं देवी लक्ष्मी। उनके प्रकट होते ही समस्त देवता और दैत्य उनकी दिव्य आभा से अभिभूत हो गए। सभी उन्हें प्राप्त करना चाहते थे, किंतु मां लक्ष्मी ने भगवान श्रीहरि विष्णु को अपना पति चुना। इस घटना का आध्यात्मिक अर्थ अत्यंत गहरा है। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन, संतुलन, मर्यादा और धर्म के प्रतीक हैं। लक्ष्मी ने उसी शक्ति को स्वीकार किया जो व्यवस्था और न्याय बनाए रखती है। इससे यह संदेश मिलता है कि जहां धर्म और संतुलन होगा, वहीं धन और समृद्धि भी स्थिर रहेगी।

शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी केवल सोने-चांदी, मुद्रा या संपत्ति का नाम नहीं है। वास्तविक लक्ष्मी वह है जो जीवन में सुख, संतोष, स्वास्थ्य, परिवार का प्रेम, उत्तम विचार, सम्मान और मानसिक शांति भी प्रदान करे। यदि किसी व्यक्ति के पास अपार धन हो लेकिन परिवार में कलह, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ और मानसिक तनाव हो, तो वह वास्तविक अर्थों में समृद्ध नहीं कहा जा सकता। इसलिए वैदिक दर्शन में लक्ष्मी को समग्र समृद्धि का प्रतीक माना गया है।

मां लक्ष्मी का चंचला स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि धन का प्रवाह आवश्यक है। जैसे बहता हुआ जल निर्मल रहता है और रुका हुआ जल दूषित हो जाता है, उसी प्रकार धन भी तभी शुभ फल देता है जब उसका सदुपयोग किया जाए। जो व्यक्ति केवल संग्रह करता है, दूसरों की सहायता नहीं करता और समाज के प्रति अपने दायित्वों को भूल जाता है, उसके जीवन में धन तो हो सकता है, लेकिन लक्ष्मी का वास्तविक आशीर्वाद नहीं होता। इसलिए भारतीय संस्कृति में दान को धन की पवित्रता बनाए रखने का सर्वोत्तम माध्यम माना गया है।

धर्मशास्त्रों में दान के अनेक रूप बताए गए हैं। अन्नदान, वस्त्रदान, गौसेवा, विद्या दान, रोगियों की सहायता, निर्धनों की सेवा और जरूरतमंदों का सहयोग ऐसे कार्य हैं जो लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माने गए हैं। दान का अर्थ केवल धन देना नहीं, बल्कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरों के जीवन में सुख और आशा का संचार करना भी है। ऐसा व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता है और उसके जीवन में समृद्धि का प्रवाह बना रहता है।

मां लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय मानी गई है। भारतीय परंपरा में घर की साफ-सफाई को केवल स्वास्थ्य से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भी जोड़ा गया है। कहा जाता है कि जहां गंदगी, अव्यवस्था और दुर्गंध होती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो जाता है। इसलिए विशेष पर्वों पर ही नहीं, बल्कि प्रतिदिन घर और पूजा स्थल की स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी गई है। बाहरी स्वच्छता के साथ-साथ मन, वाणी और व्यवहार की शुद्धता भी उतनी ही आवश्यक मानी गई है।

परिश्रम को भी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सबसे बड़ा माध्यम बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि आलस्य दरिद्रता का कारण बनता है, जबकि पुरुषार्थ समृद्धि का द्वार खोलता है। जो व्यक्ति ईमानदारी और लगन से कार्य करता है, उसके जीवन में धीरे-धीरे आर्थिक उन्नति अवश्य होती है। बिना परिश्रम के प्राप्त धन क्षणिक हो सकता है, लेकिन परिश्रम से अर्जित संपत्ति स्थायी और मंगलकारी मानी जाती है।

भारतीय संस्कृति में गृहलक्ष्मी अर्थात घर की महिला का सम्मान भी मां लक्ष्मी की कृपा से जोड़ा गया है। जिस परिवार में महिलाओं का सम्मान होता है, उनके विचारों का आदर किया जाता है और उन्हें प्रेम व सुरक्षा दी जाती है, वहां सुख-समृद्धि का वातावरण बना रहता है। इसके विपरीत जहां महिलाओं का अपमान होता है, वहां शास्त्र लक्ष्मी के अप्रसन्न होने की बात कहते हैं। इसलिए परिवार में सम्मान, प्रेम और सहयोग का वातावरण बनाए रखना भी लक्ष्मी प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूत्र माना गया है।

धार्मिक परंपराओं में कुछ ऐसे सरल उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें शुभता का प्रतीक माना जाता है। प्रतिदिन पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाने की परंपरा करुणा, सेवा और जीवों के प्रति संवेदना का संदेश देती है। गौ को पोषण और समृद्धि का प्रतीक माना गया है, जबकि कुत्ते को भोजन देना निष्ठा और संरक्षण की भावना का प्रतीक है। यह केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि प्रकृति और जीव-जंतुओं के प्रति उत्तरदायित्व का भाव भी है।

प्रत्येक शुक्रवार को श्रद्धा के साथ श्रीसूक्त, लक्ष्मी सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। वैदिक मंत्रों का नियमित उच्चारण मन को सकारात्मक बनाता है और घर के वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। पूजा के समय घी का दीपक प्रज्वलित करना तथा लाल पुष्प अर्पित करना भी मां लक्ष्मी को प्रिय माना गया है, क्योंकि लाल रंग उत्साह, ऊर्जा और मंगल का प्रतीक है।

मुख्य द्वार को घर की ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना गया है। इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल मुख्य द्वार की सफाई कर वहां स्वच्छ जल का छिड़काव करना तथा शुभ चिन्ह बनाना सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करने का प्रतीक माना जाता है। कई परिवारों में संध्या समय दीपक जलाने की परंपरा भी इसी उद्देश्य से निभाई जाती है कि घर में प्रकाश, शांति और मंगल का वातावरण बना रहे। मां लक्ष्मी का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि धन के साथ विनम्रता बनी रहनी चाहिए। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां अपार संपत्ति होने के बावजूद अहंकार ने व्यक्ति का सर्वनाश कर दिया। वहीं अनेक ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने सीमित साधनों के बावजूद ईमानदारी, सेवा और सदाचार के बल पर समाज में अमिट सम्मान प्राप्त किया। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि लक्ष्मी वहीं स्थिर रहती हैं जहां धन के साथ धर्म भी हो।

आधुनिक जीवन में भी मां लक्ष्मी के चंचला स्वरूप की शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है। आज आर्थिक परिस्थितियाँ तेजी से बदलती हैं। व्यापार, नौकरी, निवेश और बाजार की स्थिति कभी भी बदल सकती है। ऐसे समय में यह समझना आवश्यक है कि केवल आय बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि धन का विवेकपूर्ण उपयोग, बचत, निवेश, दान और नैतिक कमाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यही संतुलित दृष्टिकोण लक्ष्मी कृपा को स्थायी बनाता है। शास्त्रों का निष्कर्ष स्पष्ट है कि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए केवल पूजा-अर्चना पर्याप्त नहीं है।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmdabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

राजकोट में रिश्तों का खौफनाक अंत: बेरोजगार बेटे को पहले जबरन पिलाया तेजाब फिर गला घोंटकर हत्या का आरोप, बहू की शिकायत से खुला सनसनीखेज राज

गुजरात के राजकोट जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। गोंडल तालुका के गुंडाला गांव में 22 वर्षीय युवक की मौत को पहले आत्महत्या बताकर मामला दबाने की कोशिश की गई, लेकिन फॉरेंसिक जांच, पुलिस की सतर्कता और मृतक की नवविवाहिता पत्नी की शिकायत ने ऐसी सच्चाई उजागर की, जिसने सभी को हैरान कर दिया। आरोप है कि युवक की मां ने पहले उसके मुंह में जबरन तेजाब उड़ेल दिया और जब वह दर्द से तड़पने लगा तो उसके पिता ने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद पूरे घटनाक्रम को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई और जल्दबाजी में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। हालांकि वैज्ञानिक जांच और बहू के बयान ने पूरे मामले की दिशा बदल दी। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की विस्तृत जांच जारी है।

मृतक की पहचान 22 वर्षीय राम बांभवा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार राम की शादी करीब पांच महीने पहले 20 वर्षीय बंसी के साथ हुई थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि राम लंबे समय से बेरोजगार था और शराब पीने का आदी था। परिवार के लोगों के अनुसार वह नशे की हालत में अक्सर घर में विवाद करता था और कई बार अपने पिता से भी झगड़ा हो जाता था। लगातार होने वाले पारिवारिक विवादों ने पूरे परिवार का माहौल तनावपूर्ण बना दिया था।

एफआईआर के अनुसार 29 जून को राम अपनी पत्नी बंसी के साथ उसके मायके गया था। वहां भी उसने अत्यधिक शराब पी ली और अपने ससुर के साथ विवाद करने लगा। स्थिति बिगड़ती देख बंसी के पिता ने राम के पिता बाबू बांभवा को फोन कर उसे वापस घर ले जाने के लिए कहा। इसके बाद बाबू बांभवा अपने बेटे को लेकर घर लौट आया। अगले दिन बंसी अपने मायके में ही थी, तभी उसे सूचना मिली कि उसके पति राम ने कथित तौर पर तेजाब पीकर आत्महत्या कर ली है। इस खबर से वह स्तब्ध रह गई। परिवार ने बिना अधिक देर किए राम का अंतिम संस्कार भी कर दिया, जिससे किसी को ज्यादा सवाल पूछने का अवसर नहीं मिला।

लेकिन अंतिम संस्कार के बाद घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया। बंसी के अनुसार उसके ससुराल पक्ष के कुछ करीबी लोगों ने उसे अलग से बुलाकर पूरी घटना की अंदरूनी कहानी बताई। उन्होंने दावा किया कि राम ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। आरोप है कि 30 जून को जब राम नशे की हालत में घर पहुंचा तो उसका अपने पिता के साथ विवाद हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसकी मां मनीषा उर्फ मोटी बांभवा ने गुस्से में आकर उसके मुंह में जबरन तेजाब उड़ेल दिया।

शिकायत के मुताबिक तेजाब पेट में पहुंचते ही राम दर्द से तड़पने लगा और मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान उसके पिता बाबू उर्फ अतुल बांभवा ने कथित रूप से उसका मुंह दबा दिया और गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोप है कि घटना के बाद दोनों ने मिलकर इसे आत्महत्या का रूप देने की योजना बनाई ताकि किसी को हत्या का संदेह न हो। बंसी ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि सास-ससुर ने उसे पूरी घटना के बारे में किसी को कुछ न बताने की धमकी दी थी। उससे कहा गया कि यदि उसने सच्चाई उजागर की तो परिवार की बदनामी होगी और गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

मामले की जांच कर रही पुलिस के अनुसार शुरुआत से ही मौत की परिस्थितियां सामान्य नहीं लग रही थीं। इसी वजह से पुलिस ने केवल सामान्य पोस्टमार्टम कराने के बजाय फॉरेंसिक पोस्टमार्टम कराने का निर्णय लिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले का रुख बदल गया। जांच में मृतक के गले पर दबाव और गला घोंटे जाने के स्पष्ट निशान पाए गए। चिकित्सकों ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मौत का कारण केवल तेजाब का सेवन नहीं था, बल्कि गला घोंटने से दम घुटना भी था। इस रिपोर्ट ने आत्महत्या की कहानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।

राजकोट के पुलिस अधीक्षक विजय सिंह गुर्जर ने बताया कि वैज्ञानिक जांच और मृतक की पत्नी के बयान में कई महत्वपूर्ण तथ्य समान पाए गए, जिसके आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मृतक के माता-पिता बाबू उर्फ अतुल बांभवा और मनीषा उर्फ मोटी बांभवा को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया।

जांच अधिकारी यू.आर. डामोर के अनुसार पुलिस ने घटना से जुड़े कई महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य भी एकत्र किए हैं। कथित रूप से इस्तेमाल की गई तेजाब की बोतल बरामद कर ली गई है। घटना के समय आरोपियों द्वारा पहने गए कपड़े भी जब्त किए गए हैं ताकि उन पर मौजूद संभावित रासायनिक और जैविक साक्ष्यों की जांच की जा सके। इसके अलावा उस बिस्तर की चादर भी फॉरेंसिक टीम ने कब्जे में ली है, जिस पर पीड़ित की उल्टी के निशान पाए गए थे। इन सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि राम काफी समय से बेरोजगार था और रोजगार की तलाश कर रहा था। दूसरी ओर उसके पिता गांव में चाय का ठेला चलाकर परिवार का खर्च चलाते थे। बताया जा रहा है कि राम की शराब की लत और आए दिन होने वाले झगड़ों से पूरा परिवार परेशान था। हालांकि पुलिस का कहना है कि पारिवारिक तनाव हत्या का औचित्य नहीं बन सकता और सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं तथा हत्या के बाद सबूत मिटाने या आत्महत्या का रूप देने की साजिश में और कौन-कौन शामिल था।

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि घरेलू विवाद, नशे की लत और मानसिक तनाव यदि समय रहते नियंत्रित न किए जाएं तो वे किस तरह भयावह अपराध का रूप ले सकते हैं। परिवार, जो सुरक्षा और विश्वास का सबसे बड़ा आधार माना जाता है, उसी के भीतर यदि संवाद समाप्त हो जाए और हिंसा जगह बना ले तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं।

फिलहाल पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत हत्या, साक्ष्य छिपाने और अन्य लागू अपराधों में मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट, प्रत्यक्ष और परोक्ष गवाहों के बयान, घटनास्थल से मिले वैज्ञानिक साक्ष्य तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणों के आधार पर चार्जशीट तैयार की जाएगी। वहीं पूरे मामले में मृतक की पत्नी बंसी की शिकायत को जांच का महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है। यदि उसने साहस दिखाकर पुलिस के सामने कथित घटनाक्रम नहीं रखा होता, तो संभव है कि यह मामला आत्महत्या मानकर हमेशा के लिए बंद हो जाता। अब सभी की नजर अदालत में चलने वाली आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी है, जहां उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर इस सनसनीखेज मामले की अंतिम सच्चाई तय होगी।

पश्चिम एशियाई युद्ध के प्रभाव, मुद्रास्फीति और मंदी की बढ़ती चिंताओं के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्त है

छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान के साथ छेड़े गए युद्ध के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था लंबे समय से सुस्त है। और अगर इसका तुरंत समाधान नहीं किया गया, तो यह और भी धीमी हो जाएगी, जिससे न केवल मुद्रास्फीति बेकाबू हो जाएगी, बल्कि कई अन्य समस्याएं भी उत्पन्न होंगी।

दूसरे, पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण व्याप्त अनिश्चितता के माहौल में भारतीय अर्थव्यवस्था के तत्काल गति पकड़ने की कोई संभावना नहीं है। देश में विनिर्माण गतिविधियों की गति भी धीमी हो गई है, प्रमुख उद्योगों की विकास दर में गिरावट आई है और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं। इसके अलावा, नए व्यापारिक आदेशों और अंतरराष्ट्रीय बिक्री में आई मंदी ने रोजगार सृजन और उत्पादन की गति को धीमा कर दिया है। दूसरे शब्दों में, कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, अधिकांश क्षेत्रों में मंदी देखी जा रही है, जिसका सीधा प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। साथ ही, मांग और बाजार की स्थितियों को लेकर चिंताओं के कारण जून में निवेशकों का व्यापारिक विश्वास भी कमजोर हुआ है। विशेष रूप से विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार के प्रति संशयपूर्ण रवैया बना हुआ है। इसी वजह से विदेशी निवेश का प्रवाह लगातार तेज हो रहा है।

सर्वेक्षण से पता चलता है कि निकट भविष्य में हालात सामान्य होने की संभावना कम हो गई है। परिणामस्वरूप, अगले वर्ष उत्पादन में गिरावट आने की आशंका है। जून में उत्पादन बढ़ाने की उम्मीद रखने वाली कंपनियों का अनुपात मई की तुलना में आधा हो गया है। यह स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है।

इसलिए अक्सर देखा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में वृद्धि का हवाला देते हुए गैस, पेट्रोल, डीजल आदि की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। लेकिन जब वैश्विक कीमतें गिरती हैं, तो उपभोक्ताओं को इसका पूरा लाभ नहीं मिलता। अब जब कीमतें गिर रही हैं, तो यह बहुत जरूरी है कि आम नागरिकों के लिए आवश्यक इन ईंधनों की कीमतें कम हों।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद के विकास एवं रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जनप्रतिनिधियों एवं जनप्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में शहर एवं रेलवे से जुड़े पांच प्रमुख विकास कार्यों को शीघ्र पूरा करने के दिए निर्देशकेंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के अहमदाबाद आगमन पर आज अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अहमदाबाद महानगर के जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर शहर एवं रेलवे अवसंरचना से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है तथा परियोजना का लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2027 में सूरत–बिलिमोरा खंड पर बुलेट ट्रेन सेवा का प्रथम चरण प्रारंभ किया जाएगा। इसके पश्चात क्रमिक रूप से वापी–सूरत, अहमदाबाद तथा अंततः मुंबई तक परियोजना का विस्तार किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्र धानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अहमदाबाद सहित पूरे गुजरात में विश्वस्तरीय रेलवे अवसंरचना, आधुनिक स्टेशन, बेहतर सड़क संपर्क तथा अत्याधुनिक परिवहन सुविधाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, शहरी यातायात सुगम होगा तथा क्षेत्र के समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी।

बैठक के उपरांत केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज भारत के सेमीकंडक्टर निर्माण क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री द्वारा 28 फरवरी एवं 31 मार्च को साणंद में दो अन्य सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा चुका है।

बैठक के दौरान अहमदाबाद शहर एवं रेलवे से जुड़े निम्नलिखित पाँच प्रमुख विकास कार्यों पर निर्णय लिया गया—

ओमनगर अंडरपास (ROB) कार्य में तेजी

केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ओमनगर अंडरपास का शेष कार्य आगामी नवरात्रि महोत्सव से पूर्व हर हाल में पूरा किया जाए, ताकि नागरिकों को शीघ्र यातायात सुविधा उपलब्ध हो सके।

असारवा स्टेशन एवं टर्मिनल का व्यापक पुनर्विकास

असारवा क्षेत्र के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए असारवा स्टेशन के लिए एक समग्र मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत नया स्टेशन भवन, आधुनिक यात्री सुविधाएँ तथा डीआरएम कार्यालय सहित आसपास के रेलवे क्षेत्र का समेकित विकास कर इसे एक आधुनिक एवं सुव्यवस्थित टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा।

अहमदाबाद स्टेशन पर सारंगपुर की ओर द्वितीय प्रवेश द्वार

अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के अंतर्गत सारंगपुर दिशा से दूसरे प्रवेश द्वार एवं सड़क संपर्क के विकास पर भी सहमति बनी। इससे यात्रियों को स्टेशन तक बेहतर एवं सुगम पहुँच उपलब्ध होगी तथा आसपास के क्षेत्र का समुचित विकास संभव होगा।

शाहपुर–अहमदाबाद फ्लाईओवर परियोजना

शाहपुर–अहमदाबाद फ्लाईओवर के निर्माण के संबंध में भारतीय पुरातत्व एवं राष्ट्रीय स्मारक संरक्षण से जुड़े विषयों पर आवश्यक समन्वय स्थापित करने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस संबंध में केंद्रीय संस्कृति मंत्री से चर्चा की गई है तथा सभी आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त कर परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा।

साबरमती स्टेशन रोड विस्तार

साबरमती रेलवे स्टेशन तक बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्टेशन रो ड के विस्तार एवं समग्र विकास के लिए संयुक्त कार्ययोजना तैयार करने पर सहमति बनी। इससे यात्रियों एवं स्थानीय ना गरिकों को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध होगी।

बैठक में अहमदाबाद महानगर भाजपा अध्यक्ष श्री प्रेरकभाई शाह, महामंत्री श्री दर्शक ठाकर, श्री गौतमभाई कथीरिया, श्री उमंगभाई नायक, अहमदाबाद महानगरपालिका के महापौर श्री हितेशभाई बारोट, उपमहापौर श्रीमती अंजूबेन शाह, स्टैं डिं ग कमेटी के अध्यक्ष श्री कमलेशभाई पटेल, नगर निगम में भाजपा नेता श्री जशुभाई ठाकोर, मुख्य सचेतक श्री अतुलभाई मिश्रा तथा पार्षद श्री सनी खांचंदानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

गुजरात पुलिस ने मात्र 10 दिनों में 500 लापता लोगों को खोज निकाला

'ऑपरेशन मिलाप' की सफलता के बाद इस विशेष अभियान को 10 दिन और बढ़ाया गया

गांधीनगर : वडोदरा के एक परिवार के लिए पांच महीनों का समय अत्यंत कठिन रहा। उनकी 14 वर्षीय बेटी लापता हो गई थी। परिवार बेहद व्याकुल था। ऐसे समय में गुजरात पुलिस उनकी मदद के लिए आगे आई। गुजरात पुलिस ने 1,200 किलोमीटर दूर कर्नाटक जाकर नाबालिग बच्ची को सकुशल घर वापस लाकर उसका परिवार से पुनर्मिलन कराया।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के नेतृत्व में गुजरात पुलिस ने लापता बच्चों एवं वयस्क व्यक्तियों को खोजकर उनका उनके परिवारों से पुनर्मिलन कराने के लिए राज्यव्यापी 'ऑपरेशन मिलाप' अभियान शुरू किया था। इस अभियान को आगे 10 दिनों के लिए और बढ़ाया गया। इस चरण दौरान मात्र 10 दिनों में 500 लापता बच्चों और वयस्क व्यक्तियों को खोजने में सफलता मिली।

बच्ची 18 दिसंबर, 2025 को वडोदरा के छाणी क्षेत्र से लापता हुई थी। स्थानीय पुलिस ने कई महीनों तक जांच की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद यह मामला वडोदरा एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को सौंपा गया। टेक्निकल सर्विलांस तथा इंटेलिजेंस इनपुट्स का उपयोग करते हुए जांचकर्ताओं ने आरोपी सुनीलकुमार केसरीसिंह बारिया का पता कर्नाटक के शिवमोगा में लगाया। पुलिस के अनुसार आरोपी नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। आरोपी ने जयपुर में पुजारी का कोर्स पूरा करने के बाद नया नाम धारण कर लिया था और शिवमोगा के एक जैन मंदिर में पुजारी के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया था। वहां उसने बच्ची को अपनी पत्नी बताकर झूठी पहचान के साथ बंधक बनाकर रखा हुआ था।

जांच के लिए एक महिला पुलिस अधिकारी सहित वडोदरा एएचटीयू की पांच सदस्यीय टीम कर्नाटक पहुंची। स्थानीय पुलिस के सहयोग से टीम ने भारी बारिश के बावजूद दो दिनों तक मंदिर पर कड़ी निगरानी रखी। तीसरे दिन सुबह लगभग चार बजे जब आरोपी मंदिर पहुंचा, तब उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने बच्ची के ठिकाने की जानकारी दी। सूचना के आधार पर पुलिस ने बच्ची को सुरक्षित बरामद कर उसके परिवार से पुनर्मिलन कराया।

गुजरात के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (महिला प्रकोष्ठ, सीआईडी क्राइम) श्री अजय चौधरी ने बताया कि, "एक महीने तक चले ऑपरेशन मिलाप की सफलता के बाद हमने इस अभियान को 10 दिनों के लिए और बढ़ाया था। इस अवधि में 500 लापता बच्चों और वयस्क व्यक्तियों को सफलतापूर्वक खोजकर उनके परिवारों से मिलाया गया। यह विस्तारित अभियान 12 जून से 21 जून के बीच चलाया गया।"

उल्लेखनीय है कि इससे पहले 7 मई से 5 जून तक चलाए गए राज्यव्यापी ऑपरेशन मिलाप के दौरान गुजरात पुलिस ने 857 महिलाओं और 234 नाबालिग बालिकाओं सहित कुल 1,478 लापता नागरिकों को खोज निकाला था।

मात्र 10 दिनों तक चलाए गए इस विस्तारित अभियान के दौरान गुजरात पुलिस ने 500 और लापता नागरिकों को खोजकर उनके परिवारों से मिलाया। इनमें 288 महिलाएं, 88 बालिकाएं, 21 बालक तथा 103 पुरुष शामिल हैं। इससे 500 परिवारों के जीवन से अंधकार दूर हुआ और उनके जीवन में नई रोशनी आई।

गुजरात में लगभग 1.24 लाख करोड़ रुपए के निवेश वाले 6 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स के माध्यम से अनुमानित 50,000 से अधिक प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार का सृजन होगा

- सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए व्यापक राज्य सहायता प्रदान करने वाली समर्पित सेमीकंडक्टर पॉलिसी शुरू करने वाला गुजरात देश का प्रथम राज्य
- गुजरात में विभिन्न सहायक तथा आधारभूत उद्योगों की स्थापना द्वारा व्यापक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का हो रहा है तेज विकास

गांधीनगर : स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तथा डिफेंस संबंधी उपकरणों के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स बहुत ही आवश्यक हैं। वैश्विक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सेमीकंडक्टर क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा 'मेक इन इंडिया' के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण पर बल दिया है। सेमीकंडक्टर्स के रणनीतिक महत्व को समझते हुए इस क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भारत में 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम)' की शुरुआत की गई थी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य देश में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन (चिप उत्पादन) एवं डिसप्ले उत्पादन क्षमता को सुदृढ़ बनाना तथा आयात पर निर्भरता कम करना है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री के विजन को ध्यान में रखते हुए आज गुजरात भारत का अग्रणी सेमीकंडक्टर हब बना है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात में इस क्षेत्र के लिए समर्पित सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की गई है और ऐसी पॉलिसी शुरू करने वाला गुजरात देश का प्रथम राज्य है। गुजरात में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी आईएसएम अंतर्गत छह बड़े सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इन सभी छह प्रोजेक्ट्स में कुल मिलाकर लगभग 1.24 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और उनके माध्यम से गुजरात में लगभग 50,000 से अधिक प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की अपेक्षा है। इससे भारत की सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षमता और अधिक मजबूत होगी।

गुजरात में माइक्रोन टेक्नोलॉजी तथा केन्स सेमीकॉन के सेमीकंडक्टर प्लांट कार्यरत, शेष शीघ्र होंगे शुरू

गुजरात में मंजूर हुए छह सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन्स, केन्स सेमीकॉन, सुची सेमीकॉन और क्रिस्टल मैट्रिक्स शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स कार्यरत हो चुके हैं। माइक्रोन टेक्नोलॉजी तथा केन्स सेमीकॉन ने साणंद जीआईडीसी में अपनी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (ओएसएटी) सुविधाएँ स्थापित की हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस वर्ष फरवरी व मार्च महीने में क्रमशः माइक्रोन टेक्नोलॉजी तथा केन्स सेमीकॉन के प्लांट का उद्घाटन किया गया था और दोनों प्लांट हाल में कार्यरत हैं। उल्लेखनीय है कि सीजी सेमी शनिवार अर्थात 4 जुलाई से अपनी ओएसएटी फैसिलिटी में कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करने जा रही है, जो गुजरात की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

सुची सेमीकॉन का ओएसएटी पायलट प्लांट सूरत में पहले से ही कार्यरत है, जो भारत की सेमीकंडक्टर पैकेजिंग एवं टेस्टिंग क्षमता के विकास में योगदान दे रहा है। सुची सेमीकॉन की ओएसएटी फैसिलिटी को हाल ही में आईएसएम द्वारा मंजूरी दी गई है। धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन (फैब) सुविधा का निर्माण अपने एडवांस स्टेज में है और यह सुविधा भारत की प्रथम व्यावसायिक सेमीकंडक्टर फाउंड्री बनेगी। इसके अतिरिक्त; इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन अंतर्गत क्रिस्टल मैट्रिक्स को भी मंजूरी दी गई है, जो भारत की प्रथम व्यावसायिक मिनी एवं माइक्रो-एलईडी डिसप्ले फैब तथा पैकेजिंग इकाई स्थापित करेगी। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शीघ्र ही धोलेरा एसआईआर में शुरू होने की अपेक्षा है।

ये सभी प्रोजेक्ट्स मिलकर फैब्रिकेशन, असेंबली, पैकेजिंग, टेस्टिंग तथा उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को समाहित कर लेने वाली लचीली और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन का निर्माण करने के भारत के प्रयासों में गुजरात को अग्रणी बनाते हैं।

गुजरात में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए इकोसिस्टम का विकास

स्वीकृत हुए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स के अतिरिक्त; गुजरात में विभिन्न सहायक एवं आधारभूत उद्योगों की स्थापना द्वारा व्यापक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेज विकास हो रहा है। उल्लेखनीय है कि कई वैश्विक और स्थानीय कंपनियाँ राज्य में कार्यरत हो चुकी हैं या फिर राज्य में स्थापित होने की घोषणा कर चुकी हैं; जिनमें लिंडे, ताईवान की टीएसएमटी, जापान की टीएनएसआई व फुजीफिल्म और निप्पॉन एक्सप्रेस, जर्मनी की इन्फिनियॉन टेक्नोलॉजिस, मलेशिया की होतायी तथा अन्य कई कंपनियाँ शामिल हैं। गुजरात में ऐसे भागीदारों की उपस्थिति एक एकीकृत सेमीकंडक्टर क्लस्टर बना रही है, जो बड़े पैमाने पर फैब्रिकेशन तथा पैकेजिंग कार्य को समर्थन दे सकता है।

इसके अतिरिक्त; गुजरात इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी, जो भारत सरकार की स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स (एसपीईसीएस) योजना के अनुरूप है, सेमीकंडक्टर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन गतिविधियों के समग्र क्षेत्र को समर्थन देती है। इसमें कम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, पैकेजिंग और टेस्टिंग सुविधाएँ, मटेरियल सप्लायर्स, इक्विपमेंट प्रोवाइडर्स, अल्ट्रा-हाई प्योरिटी गैस के उत्पादक तथा सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए विशेष केमिकल्स शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में आईएसएम 2.0 के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी है, जिसे शीघ्र ही अंतिम मंजूरी के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता को और अधिक गहरी बनाएगा। वित्तीय प्रोत्साहनों, इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहलों, इकोसिस्टम को प्रोत्साहन देने वाली पहलों तथा पारदर्शी शासन द्वारा गुजरात का उद्देश्य स्वयं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक सेमीकंडक्टर हब बनाना है, जो राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक हो।

केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की तथा इंजीनियरों एवं निर्माण टीमों से किया संवाद

केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई–अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत निर्माणाधीन अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा कर परियोजना के प्रगति कार्यों की समीक्षा की तथा इस महत्वाकांक्षी परियोजना में कार्यरत इंजीनियरों एवं निर्माण टीमों से संवाद किया।

दौरे के दौरान श्री वैष्णव ने स्टेशन भवन एवं उससे संबंधित आधारभूत संरचना के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद खंड में कॉरिडोर के कुछ सबसे जटिल इंजीनियरिंग कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें मौजूदा रेलवे लाइनों एवं फ्लाईओवरों के ऊपर अनेक क्रॉसिंग का निर्माण शामिल है। उन्होंने बहुमंजिला स्टेशन भवन तथा एप्रोच अवसंरचना की प्रगति का भी अवलोकन किया और अधिकारियों को परियोजना को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के लिए निर्माण कार्य की गति बनाए रखने के निर्देश दिए।

केंद्रीय मंत्री ने निर्माण स्थल पर कार्यरत इंजीनियरों एवं निर्माण टीमों से मुलाकात कर उनके कार्य, अनुभव एवं कुशलक्षेम की जानकारी ली तथा उनकी समर्पित भावना, प्रतिबद्धता और अथक परिश्रम की सराहना की। उन्होंने निर्माण कार्य की निरंतर प्रगति के लिए टीमों की प्रशंसा करते हुए उन्हें सुरक्षा, गुणवत्ता तथा इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के सर्वोच्च मानकों को बनाए रखते हुए कार्य जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया।

श्री वैष्णव ने कहा कि अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन को एक पूर्णतः एकीकृत मल्टीमॉडल परिवहन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो बुलेट ट्रेन स्टेशन को पारंपरिक रेलवे स्टेशन, मेट्रो तथा शहर की बस सेवाओं से सहज रूप से जोड़ेगा।

उन्होंने यह भी बताया कि स्टेशन की डिजाइन अहमदाबाद की सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक 'पतंग' से प्रेरित है, जिसमें शहर की सांस्कृतिक विरासत और विश्वस्तरीय अवसंरचना का उत्कृष्ट समन्वय किया गया है।

यह दौरा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत उन्नत इंजीनियरिंग, एकीकृत परिवहन अवसंरचना तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप यात्री सुविधाओं के साथ मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है।

साणंद की सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हैट्रिक : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 7600 करोड़ रुपए के अत्याधुनिक सीजी सेमीकॉन के ओएसएटी प्लांट का शुभारंभ किया

▸▸ भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा के लिए यह एक ऐतिहासिक दिवस है, साणंद में सीजी सेमी ओएसएटी सुविधा चिप उत्पादन इकोसिस्टम को मजबूत करेगी, तकनीकी आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देगी और वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में भारत का स्थान मजबूत करेगी : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

- ▸▸ सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम तेज गति पकड़ रहा है, स्टेप बाय स्टेप, ब्रिक बाय ब्रिक और अब चिप बाय चिप
- ▸▸ भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग का विस्तार रातोंरात नहीं हुआ, यह इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जो पिछले एक दशक में भारत में हुई है
- ▸▸ पहले प्रोडक्ट्स, फिर कंपोनेंट्स और अब सेमीकंडक्टर्स, भारत समग्र इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन का निर्माण कर रहा है, यह विकसित भारत का रोडमैप है, यह मेक इन इंडिया का अगला चरण है
- ▸▸ हमारा लक्ष्य चिप डिजाइन से लेकर फैब्रिकेशन और पैकेजिंग तक, भारत में संपूर्ण सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाना है
- ▸▸ भारत के युवा मेड इन इंडिया चिप्स के साथ एआई, रोबोटिक्स और नेक्स्ट-जेन टेक क्रांति को ऊर्जा देंगे
- ▸▸ **वैश्विक सेमीकंडक्टर मैप पर चमकेगा गुजरात : प्रतिदिन 1.5 करोड़ चिप्स की क्षमता के साथ अगले 5 वर्षों में 5000 से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन होगा**
- ▸▸ **प्रधानमंत्री ने प्रथम चिप शिपमेंट ग्लोबल जायंट रेनेसास को सौंपा**
- ▸▸ **प्रधानमंत्री के विजनरी नेतृत्व में यह दशक भारत के लिए सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर्स का 'टेकेड' : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल**
- ▸▸ **हमारी सेमीकंडक्टर चिप्स न केवल भारत में इस्तेमाल होगी, बल्कि जापान, अमेरिका और यूरोप में भी उसका निर्यात होगा : श्री अश्विनी वैष्णव**

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (ओएसएटी) फैसिलिटी का उद्घाटन किया।

इस अवसर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने इस लॉन्चिंग को देश के अपने लक्ष्यों के प्रति अटूट संकल्प का प्रमाण बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश बिना किसी झिझक के अपने मजबूत संकल्पों को वास्तविकता में रूपांतरित करता है। श्री मोदी ने दृढ़ता से कहा, "आज का यह कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है, वो करके दिखाता है।"

आधे दशक पहले शुरू किए गए रणनीतिक विजन को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने देश को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक हब में बदलने के मुख्य उद्देश्य का उल्लेख किया। स्थानीय डिजाइन और स्थानीय उत्पादन की व्यापक रणनीतियों से प्रेरित होकर उन्होंने इस तीसरी बड़ी फैसिलिटी में व्यावसायिक चिप पैकेजिंग की आधिकारिक शुरुआत का जश्न मनाया।

श्री मोदी ने कहा, "हम 'डिजाइन इन इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' के मूल मंत्र के साथ सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं।" इस प्रोजेक्ट के तेज विकास की समयरेखा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने वर्ष 2024 में इसके शिलान्यास अवसर को याद किया और अगस्त 2025 तक चिप टेस्टिंग की तेज शुरुआत की प्रशंसा की। उन्होंने योजना से लेकर बड़े पैमाने पर उत्पादन तक के इस तेज सफर का श्रेय प्रोजेक्ट से जुड़े अनेक सहयोगियों के निरंतर समर्पण और ध्यान को दिया। श्री मोदी ने आगे कहा, "शिलान्यास से लेकर उत्पादन तक का यह असाधारण सफर निश्चित रूप से अनेक साथियों की कड़ी मेहनत का परिणाम है।"

सभा को संबोधित करने से पहले अपनी व्यक्तिगत मुलाकातों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने फैसिलिटी में तैनात समर्पित कर्मचारियों के साथ बातचीत के अपने अनुभव साझा किए। एग्जीबिशन के दौरे के दौरान अनेक युवा पेशेवरों के साथ सीधा संवाद करने के बाद, उन्होंने उनकी अद्भुत ऊर्जा, आशावाद और सकारात्मक दृष्टिकोण की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, "आज मैंने जितने भी युवा साथियों से बातचीत की, वे सभी पूरी तरह से आत्मविश्वास भरे हुए हैं।"

नवनिर्मित फैसिलिटी को अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक बताते हुए प्रधानमंत्री ने स्थानीय, जापानी और थाई उद्योग साझेदारों के संयुक्त प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने इस उद्यम को केवल एक साधारण बिजनेस वेंचर से कहीं अधिक बताया और इसे तकनीक, भरोसे और सरहद पार की साझेदारी के एक मजबूत मॉडल के रूप में रेखांकित किया। श्री मोदी ने जोर देकर कहा, "यह एकीकृत साझेदारी भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा को पूरी तरह से नई गति देने जा रही है।"

गत सवा दो वर्ष में हासिल किए गए बड़े स्केल की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने सालाना 20 करोड़ यूनिट सप्लाई करने की क्षमता वाले सक्रिय वाणिज्यिक उत्पादन में प्रवेश करने की प्रशंसा की। सालाना 500 करोड़ यूनिट तक पहुंचने के टीम के महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर संपूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने इस तेज प्रगति का श्रेय देशव्यापी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम की तेज रफ्तार को दिया। श्री मोदी ने कहा, "मैं पूरी टीम को, राज्य सरकार को और पूरे देश को इस सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप, ब्रिक बाय ब्रिक और चिप बाय चिप बनाने के लिए बधाई देता हूं।"

उपस्थित उद्योग विशेषज्ञों और युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने वैश्विक औद्योगिक इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि असली उत्पादन शक्ति केवल अलग-अलग फैक्ट्रियां स्थापित करने से नहीं आती। सिलिकॉन वैली, सिंचु साइंस पार्क और सुकुबा साइंस सिटी जैसे प्रसिद्ध टेक हब का उल्लेख करते हुए उन्होंने व्यापक और एकीकृत इकोसिस्टम विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने कहा, "आज साणंद ऐसे शक्तिशाली क्लस्टर स्थापित करने के लिए उसी दिशा में दृढ़तापूर्वक अपने कदम आगे बढ़ा रहा है।"

स्थानीय स्तर पर मजबूत इकोसिस्टम के तेज से उभरने की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किस प्रकार माइक्रोन, केन्स और सीजी सेमी जैसे अग्रणी कंपनियों ने कुछ ही महीनों में इस क्षेत्र में एक साथ उत्पादन शुरू किया है। आने वाले समय में विशिष्ट केमिकल उत्पादक, टेस्टिंग लैब्स, डिजाइन सेंटर्स और गतिशील नए स्टार्टअप्स के आगमन का विचार करते हुए उन्होंने विस्तार से समझाया कि कैसे स्थानीय उद्योग व्यापक आर्थिक और रोजगार के अवसरों में कई गुना वृद्धि करते हैं। श्री मोदी ने जोर देकर कहा, "यह क्लस्टर की असली ताकत है, जहां एक उद्योग दूसरे दस उद्योगों को जन्म देता है और अंत में पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बदल देता है।"

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आए उभार को लेकर देश और दुनिया में दिख रहे भारी उत्साह का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने इस गलतफहमी को दूर किया कि यह तीव्र वृद्धि कोई अलग घटना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान विस्तार वास्तव में पिछले 10 वर्षों में बनाई गई दीर्घकालिक तकनीकी नीतियों से निकली एक सुनियोजित प्रगति है। श्री मोदी ने कहा, "यह पिछले एक दशक में भारत में आई इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का स्वाभाविक अगला कदम है।"

स्थानीय उत्पादन की इस सफलता के मूल के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने अतीत में आयातित स्मार्टफोन पर निर्भरता की तुलना वर्तमान उत्पादन में उछाल के साथ की। आउटपुट में आश्चर्यजनक 33 गुना वृद्धि की चर्चा करते हुए उन्होंने गर्व से कहा कि भारत मोबाइल फोन क्षेत्र में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश बन गया है। श्री मोदी ने कहा, "हमने अंततः इन अद्भुत मील के पत्थरों को हासिल करने के लिए जान-बूझकर अपना सफर मोबाइल फोन उत्पादन से शुरू किया था।"

हाल के वर्षों में स्थानीय इकोसिस्टम की व्यापक सफलता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने इस पूरे क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि के आंकड़े साझा किए। उन्होंने बताया कि कुल उत्पादन वर्ष 2014 के स्तर की तुलना में लगभग 7 गुना बढ़ा है। साथ ही, कुल निर्यात में 11 गुना का भारी उछाल आया है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा, "हमने समग्र इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन इकोसिस्टम को सफलतापूर्वक और व्यापक रूप से मजबूत बनाया है।"

सरकार के रणनीतिक रोडमैप के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि हमारा प्रयास, केवल फाइनल प्रोडक्ट में आत्मनिर्भरता तक सीमित नहीं है। हमारा प्रयास कंपोनेंट्स में भी आत्मनिर्भरता की तरफ है। वैश्विक टेक्नोलॉजी को ताकत देने वाली चिप्स का उत्पादन करने की प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने संपूर्ण एंड-टू-एंड स्थानीय वैल्यू चेन की रूपरेखा दी। श्री मोदी ने कहा, "पहले प्रोडक्ट, फिर कंपोनेंट्स और अब सेमीकंडक्टर, यह मेक इन इंडिया का निर्णायक अगला चरण है।"

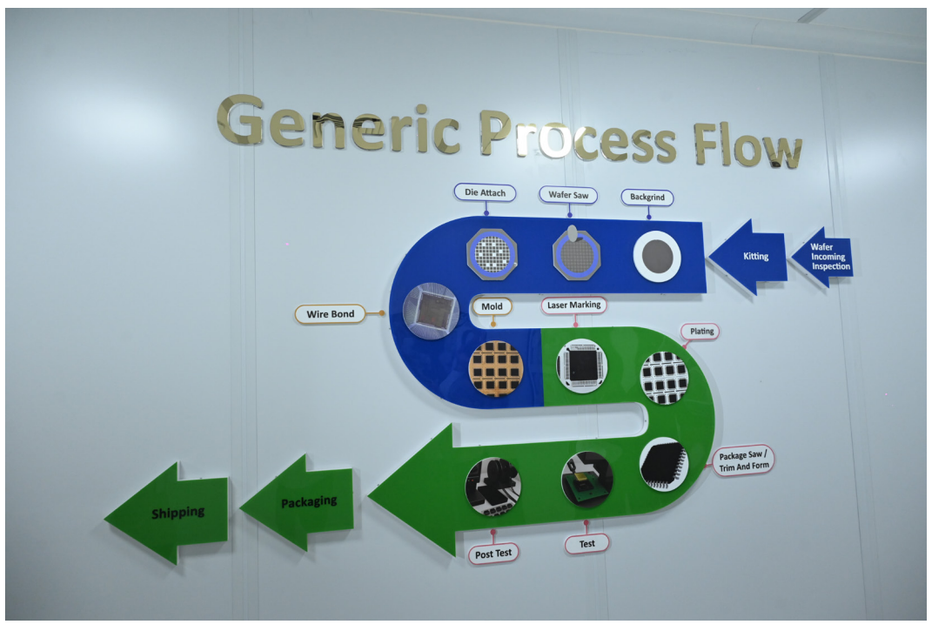

इकोसिस्टम के भविष्य के चरणों का मैप प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री ने पूरी सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने के लिए हाई-टेक मटेरियल्स और क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता की खासी जरूरत पर बल दिया। उन्होंने डिजाइन से लेकर पैकेजिंग तक फैले स्थानीय नेटवर्क की कल्पना करते हुए एआई और रोबोटिक्स में अत्याधुनिक क्रांति के लिए इन लोकल चिप्स का उपयोग करने के लिए युवा पीढ़ी पर अपार विश्वास व्यक्त किया। श्री मोदी ने जोर देकर कहा, "हमारे युवा केवल मेड इन इंडिया चिप्स का उपयोग करके नेक्स्ट जेन टेक क्रांति को भी गति देगा।" युवा वर्ग को अपना संदेश देते हुए प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक उदाहरणों पर रोशनी डाली, जो दिखाते हैं कि किस प्रकार बड़े औद्योगिक परिवर्तन हमेशा रोजगार के अभूतपूर्व अवसर पैदा करते हैं। पहले आई आईटी और स्मार्टफोन की क्रांति से खुले विशाल अवसरों के समान ही वर्तमान तकनीकी लहर से भी विशाल अवसर खुलेंगे। श्री मोदी ने कहा, "सेमीकंडक्टर और एआई क्रांति का यह दौर अनुसंधान और डिजाइन से लेकर सप्लाई चेन मैनेजमेंट तक, अनेक अवसर ला रहा है।"

भविष्य की वर्कफोर्स को लगातार सामंजस्य बिठाने के लिए चुनौती देते हुए प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि आधुनिक समय में प्रासंगिक बने रहना नए कौशल सीखने और नए आइडिया विकसित करने पर निर्भर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा खोले गए विशाल नए आयामों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से इन उभरते अवसरों को अत्यंत उत्साह के साथ भुनाने का अनुरोध किया। श्री मोदी ने दृढ़तापूर्वक कहा, "भारत के युवाओं को कुछ नया सीखने और उसे लागू करने का यह अद्भुत अवसर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए।" इस तकनीकी प्रगति के सामाजिक प्रभावों को दर्शाते हुए प्रधानमंत्री ने इस नई फैसिलिटी में सक्रिय रूप से काम कर रहीं आदिवासी समुदाय की युवतियों की प्रेरणादायी बातें साझा कीं। साधारण पृष्ठभूमि और आईटीआई की पढ़ाई से लेकर मलेशिया में अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने तक की उनकी यात्रा से वे गहराई से प्रभावित हुए और उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इन बेटियों ने पहले कभी अपने गृह राज्य से बाहर की यात्रा नहीं की थी, इसके बावजूद दुनिया की सबसे आधुनिक उत्पादन प्रक्रियाओं को चलाने में अहम भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा, "वास्तव में, असाधारण सपने देखने वालीं ये बेटियां आज 'मेड इन इंडिया' चिप उत्पादन प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा हैं।" अपने संबोधन के समापन में प्रधानमंत्री ने दोहराया कि देश संपूर्ण विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अनेक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के समय पर साकार हो जाने की कुछ महीने पहले कही गई अपनी बात के पूरा होने पर खुशी व्यक्त की। वैश्विक निवेशकों को संपूर्ण नीतिगत स्थिरता, स्पष्ट निर्णय लेने की क्षमता और शानदार क्रियान्वयन गति का आश्वासन दिया और सुनियोजित आर्थिक सुधारों की तेज गति का वादा किया। श्री मोदी ने कहा, "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ, 140 करोड़ भारतीय 2047 तक देश को निश्चित रूप से विकसित बनाएंगे।"

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सीजी सेमीकॉन के कमर्शियल प्रोडक्शन प्रारंभ होने के अवसर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत के के लिए प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण बताया। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्लांट भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाएगा तथा देश के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और अधिक वेग देगा। उन्होंने यह भी कहा कि सीजी सेमीकॉन के इस प्लांट के माध्यम से 5 हजार से अधिक प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार का सृजन होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के लगातार 12 वर्ष के सुशासन कार्यकाल के दौरान भारत ने फ्रेजाइल फाइव इकोनॉमी से निकलकर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की विशिष्ट पहचान प्राप्त की है। श्री पटेल ने आर्थिक विकास की इस यात्रा में मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्ट पावर तथा टेक्नोलॉजी लैंडस्केप में अनेक नए क्षेत्रों के द्वार खुलने पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने जोड़ा कि सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर्स में प्रधानमंत्री के विजन से भारत का प्रभाव बढ़ा है। कोरोना महामारी के दौरान जब पूरी ग्लोबल चेन संकट में थी, तब प्रधानमंत्री ने भारत को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में ग्लोबल हब बनाने का जो संकल्प किया था, उसे आज "जो कहना, वह करना" के मंत्र के साथ साकार किया है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के विजन से देश की प्रथम स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी धोलेरा में विश्वस्तरीय सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित हो रहा है। इतना ही नहीं, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में गुजरात को फ्यूचर रेडी बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2022 में देश की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी घोषित करने का गौरव भी गुजरात ने प्राप्त किया है।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करने में आत्मनिर्भरता को मुख्य आधार बताते हुए कहा कि श्री नरेन्द्रभाई मोदी के नेतृत्व मंर आत्मनिर्भरता अब ग्लोबल चैलेंजेस का सॉल्यूशन बन गई है। उन्होंने विकसित गुजरात से विकसित भारत के निर्माण में सहयोग करने के लिए सभी का आह्वान भी किया।

केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के सेमीकॉन मिशन की तकनीकी यात्रा तथा ढाँचागत सुविधाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प से आज भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक वास्तविक उपलब्धि बनी है। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और उनकी टीम की अद्भुत कार्यक्षमता के कारण मार्च 2024 में शिलान्यास होने के बाद केवल 27 महीनों के रिकॉर्ड समय में साणंद के इस तीसरे प्लांट में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है। इस प्लांट में बनाई जाने वाली चिप्स का केवल भारत की कारों व स्कूटरों में ही उपयोग नहीं होगा, बल्कि यहां से उन्हें जापान, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में भी निर्यात किया जाएगा, जिसके द्वारा वैश्विक स्तर पर भारत की टेक्नोलॉजी का डंका बजाया जाएगा। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को आज 13 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बना दिया गया है, जिसके द्वारा 25 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

श्री अश्विनी वैष्णव ने विशेष गर्व की अनुभूति करते हुए कहा कि देश के कोने-कोने से आए युवा, जिनमें झारखंड, छत्तीसगढ़ और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों के तथा विशेष रूप से गांवों से पहली बार मलेशिया प्रशिक्षण के लिए भेजी गई बेटियों द्वारा आज यहां रियल चिप्स बनाई जा रही हैं। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 315 यूनिवर्सिटियों में विशेष कोर्स शुरू कर दिए गए हैं और हजारों नवयुवाओं को डिजाइन का प्रशिक्षण दिया गया है। भारत द्वारा बहुत ही तेज गति से प्रगति की जा रही है। आने वाले महीनों में और 2 प्लांट शुरू किए जाएंगे, यानी कि वर्ष 2026 समाप्त होने तक भारत में कुल 5 सेमीकंडक्टर प्लांटोस में उत्पादन प्रारंभ किया जाएगा, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है।

सीजी पावर के चेयरमैन श्री वेल्लायन सुब्बैया ने स्वागत संपबोधन में इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। साणंद फैसिलिटी से हमारा प्रथम कमर्शियल कन्साइनमेंट जापान की रेनेसास कंपनी के वैश्विक ग्राहकों के लिए रवाना किया गया है, जो वैश्विक स्तर पर हमारी गुणवत्ता एवं क्षमता को सिद्ध करता है। "काम बोलता है" और "एकता में ही शक्ति है" के मंत्र को सार्थक करते हुए यह प्रोजेक्ट केवल एक फैक्टरी का निर्माण नहीं है, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन में भारत को स्थापित करने तथा देश के एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कौशल को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि भारत की उड़ान में ही हमारी उड़ान है। श्री सुब्बैया ने गुजराती कहावतों का उल्लेख कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया।

उल्लेखनीय है कि 7,600 करोड़ रुपए के निवेश से प्रारंभ हुआ यह प्रोजेक्ट देश और दुनिया के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का नया अध्याय लिखेगा। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' अंतर्गत गुजरात के औद्योगिक हब साणंद में उद्घाटित यह प्लांट एक और ऐतिहासिक उपलब्धि सिद्ध होगा।

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सेमीकंडक्टर ओएसएटी प्लांट के क्लीन रूम तथा एक्सपीरियंस सेंटर का दौरा किया और इंजीनियरों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री के करकमलों से पहली चिप शिपमेंट ग्लोबल जायंट रेनेसास को सौंपी गई। इस समारोह में गुजरात के उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदीशभाई विश्वकर्मा, सांसद श्री दिनेशभाई मकवाणा, स्थानीय विधायक, राज्य के मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव श्री जयंती रवि, वरिष्ठ अधिकारी, रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रेसिडेंट श्री मालिनी नारायणमूर्ति, कलेक्टर श्री भव्य वर्मा, जिला विकास अधिकारी श्री विदेह खरे, सीजी सेमीकॉन के अधिकारी तथा सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी और युवा उपस्थित रहे।

परियोजना की प्रमुख विशेषताएं और आंकड़ों में विवरण :

साणंद का यह नया प्लांट सेमीकंडक्टर के वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति मजबूत बनाने में कुंजीरूपी भूमिका निभाएगा। प्रोजेक्ट के प्रमुख विवरण निम्नानुसार हैं :

कुल निवेश : 7,600 करोड़ रुपए (केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा फरवरी 2024 में मंजूरी)।

उत्पादन क्षमता : दोनों प्लांट मिलकर पूर्ण क्षमता पर पहुंचने के बाद प्रतिवर्ष 5 अरब (5 बिलियन) तथा प्रतिदिन 1.5 करोड़ चिप्स का उत्पादन करेंगे।

रणनीतिक भागीदारी : इस प्रोजेक्ट में सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन्स लिमिटेड की सब्सिडयरी सीजी सेमी, जापान की रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स तथा थाईलैंड की स्टार माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स के बीच संयुक्त भागीदारी है।

रोजगार सृजन : प्लांट में हाल में 300 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि अगले 5 वर्ष में 5,000 प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार अवसरों का सृजन होगा।

चिप्स के प्रकार तथा उपयोग : प्लांट में क्यूएफएन तथा क्यूएफबी जैसी लीगेसी चिप्स एवं अत्याधुनिक एफसी-बीजीए और एफसी-सीएसपी चिप्स का निर्माण होगा, जो ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल संसाधनों, 5जी कम्युनिकेशन तथा पावर एप्लिकेशन क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगी।

नमो गुजरात कौशल्य एवं रोजगार मिशन के तहत अहमदाबाद में 'उद्योग एकेडेमिया-सेक्टर स्किल काउंसिल्स आउटरिच' कार्यक्रम आयोजित

▸▸ विकसित भारत और विकसित गुजरात के लिए विश्व स्तरीय उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण अनिवार्य : श्री लोचन सेहरा, सचिव, श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

▸▸ कौशल विकास, इंटर्नशिप और रोजगार के लिए डीएसडी, केएसयू, जीटीयू और गिफ्ट सिटी ने एनएसडीसी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए

गांधीनगर : गुजरात सरकार के श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अधीनस्थ कौशल विकास निदेशालय (डीएसडी) और रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय (डीईटी) ने गत गुरुवारर, 2 जुलाई को अहमदाबाद के ले मेरिडियन होटल में नमो गुजरात कौशल एवं रोजगार मिशन (एनजीकेआरएम) के तहत 'उद्योग-एकेडेमिया – सेक्टर स्किल काउंसिल्स आउटरिच कार्यक्रम' आयोजित किया।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों और सेक्टर स्किल काउंसिल्स के बीच मजबूत सहयोग स्थापित करना तथा नमो गुजरात कौशल एवं रोजगार मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगार योग्यता परिवर्तन (पीएम-सेतु) योजना, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना तथा मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना को लेकर जागरूकता पैदा करना था।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के सचिव श्री लोचन सेहरा ने कहा कि विकसित भारत और विकसित गुजरात के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कुशल मानवबल बहुत ही आवश्यक है। विश्व स्तरीय और उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण के जरिए ही वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी युवा तैयार किए जा सकते हैं। इसके अलावा, उन्होंने उद्योगों उद्योगों से सरकार के विभिन्न कौशल मिशनों में सक्रिय भागीदार बनने की अपील की।

इस अवसर पर कौशल विकास, पाठ्यक्रम विकास, इंटर्नशिप, प्रमाणपत्र और रोजगार क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए डीएसडी, कौशल्य - द स्किल यूनिवर्सिटी (केएसयू), गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (जीटीयू) और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने अलग-अलग प्रेजेंटेशन के जरिए राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया (ईएसएससीआई), ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल (एएसडीसी) और लॉजिस्टिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल (एलएससी) के प्रतिनिधियों ने विभिन्न क्षेत्रों में कौशल की मांग, रोजगार के अवसर, उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों और उद्योग-अकादमिक सहयोग पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिए।

इस अवसर पर एनएसडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) श्री अरुण पिल्लई, कौशल्य – द स्किल यूनिवर्सिटी के महानिदेशक प्रो. एस.पी. सिंह, डीएसडी के निदेशक श्री के.जे. राठोड़, उप निदेशक श्री निपुण रावल, डेलॉइट के निदेशक श्री प्रियंक पटेल, भारतीय कॉर्पोरेट कानून सेवा (आईसीएलएस) से श्रीमती अंकिता लाहोटी और एनएसडीसी के प्रतिनिधि श्री राकेश कुमार सहित राज्यभर से 200 से अधिक उद्योगों, उद्योग संगठनों, यूनिवर्सिटियों, शैक्षणिक संस्थानों, रोजगारदाताओं तथा सेक्टर स्किल काउंसिल्स के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

नागालैंड में दुकानें बिना दुकानदारों के चलती हैं, ग्राहक खुद खरीदारी करते हैं और ईमानदारी से भुगतान करते हैं

(छनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। आज के उथल-पुथल भरे कलियुग में, जहाँ धोखाधड़ी और विश्वासघात के मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, भारत के एक राज्य में "राम राज्य" जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। उत्तर-पूर्वी भारत के खूबसूरत राज्य नागालैंड में लोग इतने ईमानदार हैं कि वहाँ की स्थानीय दुकानों में किसी चौकीदार या दुकानदार की आवश्यकता ही नहीं है। ग्राहक स्वयं दुकान पर आते हैं, अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं और ईमानदारी से कैश बॉक्स में या ऑनलाइन स्कैनर के माध्यम से भुगतान करके चले जाते हैं।

यह व्यवस्था नागालैंड के छोटे गांवों और कुछ शहरों में बहुत आम है। यहां दुकानें दिन भर खुली रहती हैं और उनके मालिक अपने अन्य कामों में व्यस्त रहते हैं। ग्राहक दुकान पर आकर मूल्य सूची या स्कैनर से सामान्य मूल्य की जांच करते हैं, फिर नकद राशि जमा करते हैं और यदि उन्हें छुट्टा वापस लेना हो तो वे स्वयं गिन लेते हैं। दुकानदार शाम को आते हैं और केवल हिसाब-किताब करते हैं। हैरानी की बात है कि यहां चोरी या गबन के मामले न के बराबर या न के बराबर हैं। नागालैंड की इस अनूठी परंपरा के पीछे आदिवासी संस्कृति और मजबूत सामुदायिक मूल्य जिम्मेदार हैं।

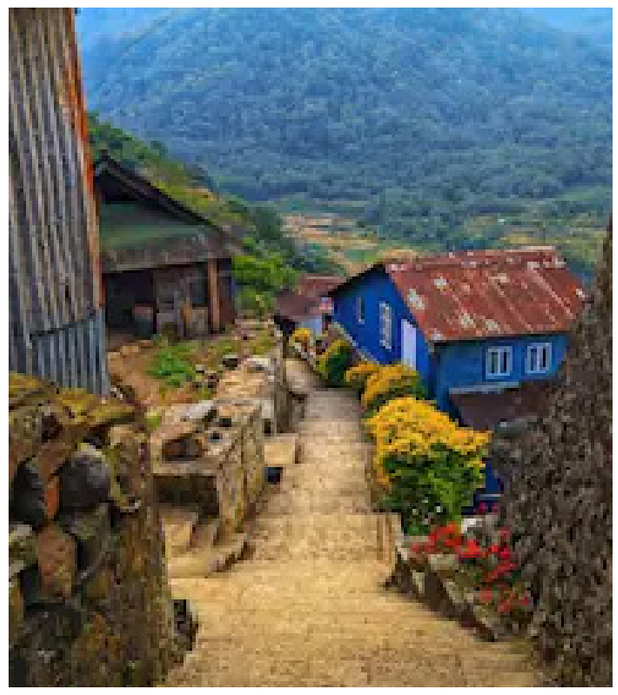

यहां लोग एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और समाज में नैतिकता का स्तर इतना ऊंचा है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी गलत करने से पहले सौ बार सोचता है। दुकानदार ही नहीं, टैक्सी चालक और होमस्टे मालिक भी पर्यटकों से अतिरिक्त शुल्क नहीं लेते। इस प्रकार, नागालैंड की यह व्यवस्था पूरे देश के लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करती है।